स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–19, अंक–9, भाद्रपद–आश्विन 2068, सितम्बर 2011

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्रा, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा-4

भारत के सुरक्षा अधिकारियों ने देश के सामने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा कि उन्हें आतंकवादी हमलों के बारे में खुफिया जानकारी होने के बावजूद हमले रोकने में कामयाबी नहीं मिली।

अनुक्रम

आवरण लेख
चुनौतियों के आगे ढ़ेर नेतृत्व
– विक्रम उपाध्याय /4

सामयिकी
नए संघर्ष की शुरूआत
– बलवीर पुंज /7

जन आंदोलन
देश की जनता जाग चुकी है
– निरंकार सिंह /10

अंतर्राष्ट्रीय
चीन का राजनीतिक हथियार
– ब्रह्मा चेलानी /13

बाढ़
बाढ़ ग्रस्त ग्रामीण इलाकों की पीड़ा
– भारत डोगरा /15

दृष्टिकोण
मुंबई की बाढ़ को रोकने का सिंगापुरी तरीका
– डॉ. अश्विनी महाजन /18

अर्थव्यवस्था
वैश्विक कर्ज संकट से मुश्किलें
– डॉ. जयंती भंडारी /20

विचार–विमर्श
पुराने उपायों से संभव नहीं समाधान
– आलोक पुराणिक /23

मुद्दा
क्यों नहीं सफल है एयर इंडिया...?
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /25

लेख
भारतीय परिवार
– रेणु पुराणिक /27

स्वास्थ्य चिंतन
पर्यावरण एवं स्वास्थ्य – आयुर्वेदीय दृष्टिकोण
– डॉ. योगेश चन्द मिश्र /29

पाठकनामा/2, रपट/33, आंदोलन/35

पाठकनामा

शिक्षा बनाम वाइन कल्चर

मुझे स्वदेशी पत्रिका से काफी कुछ सीखने को मिला है और पत्रिका को पढ़कर देश की समस्याओं के बारे में पता चलता है। आज हमें आजादी प्राप्त हुए 64 वर्ष पूरे हो चुके हैं लेकिन शिक्षा के विषय में हम विकसित देशों के मुकाबले काफी पीछे है। सरकार ने जनता को लुभाने के लिए आठवीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, इसका नियम बना दिया है परंतु सरकारी स्कूलों का क्या हाल है यह किसी से छिपा नहीं है। आज भी सरकारी शिक्षक हो या नगर निगम का कर्मचारी या फिर सिपाही सभी अपनी नौकरी को ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। हां एक विकास जरूर हो रहा है और वह है मदिरा की बिक्री। आज देश की राजधानी दिल्ली के वासियों पर वाइन कल्चर दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका अंदाजा आबकारी विभाग की वाइन की बिक्री से हो रही मोटी कमाई से लगाया जा सकता है। एक्साइज डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष वाइन की बिक्री में 60 फीसदी से भी अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब महिलाएं भी शराब पीने में दिलचस्पी ले रही हैं क्योंकि नामी गिरमी शराब कंपनियां अपने वाइन के विज्ञापन पर लुभावने वाला प्रचार करती है जिसके कारण युवा वर्ग वाइन कल्चर को अपनाने लगा है। क्या हो गया है सरकार को, जहां सरकार का फर्ज बनता था कि युवा वर्ग को ठीक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। वही दूसरी ओर सरकार अपनी कमाई के आंकड़ों को प्रस्तुत करती रहती है। सरकार को अपनी गलती सुधारी चाहिए अन्यथा आने वाला युवा वर्ग कही शिक्षा में विकास न करके वाइन कल्चर में विकास न कर जाए।

– विनोद कुलियाल, सेक्टर–3, आर.के. पुरम्, नई दिल्ली

लापरवाह अधिकारियों और लापरवाह नेताओं को मिलें दण्ड

एक बार फिर देश आतंकवाद की चपेट में आ गया। दिल्ली में हाई कोर्ट के बाहर हुए विस्फोट से देश की जनता बार–बार, देश के नेताओं से और सुरक्षा अधिकरियों से गुहार लगती है कि आखिर कब तक हम इन हादसों के शिकार होते रहेंगे। हाई कोर्ट में सीसी टीवी कैमरे या फिर खराब मेटल डिटेक्टर, कुल मिलाकर यह स्पष्ट हो गया कि आधे अधूरे सुरक्षा इंतजामों के चलते ही यह घटना घटी। पुलिस प्रशासन अपनी कमी को न बताकर गेंद एक–दूसरे के पाले में डालने को लगे हुए हैं। होना यह चाहिए था कि हाई कार्ट में सुरक्षा की जिम्मेदारी किस को दी गई थी, उन सबको तुरंत निलंबित कर देना चाहिए था। क्योंकि हर बार सुरक्षा की लापरवाही से यह घटना होती रहती है। हाई कोर्ट में मारे गए परिवार वाले भी मंत्रियों और सुरक्षा अधिकारियों से यही गुहार लगा रहे थे कि आखिर कब तक हम इन आतंकवादियों की गतिविधियों का शिकार होंगे – परंतु सरकार खामोश बैठी है।

– श्याम सलोना, युवा पत्रकार, पटेल चेस्ट (दिल्ली यूनिवर्सिटी)

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

'नोट के बदले वोट' ऐसे कार्यों में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी सांसद या विधायक को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए।"

– अन्ना हजारे

नेताओं पर टिप्पणी करने से अगर कुछ बदलाव हुआ, तो यह करने में कुछ गलत नहीं था। वह जनता की आवाज थी। किसी को दुखी करने का मेरा मकसद नहीं था और मैं संसद का सम्मान करती हूं।

– किरन बेदी

मैंने कुछ भी गलत या गैरकानूनी काम नहीं किया है। मैंने अपने दो दशक लंबे सार्वजनिक जीवन में उठे सभी सवालों के जवाब पूरी प्रामाणिकता के साथ दिए हैं।

– रामदेव बाबा

संपादकीय

जनता को जेब में रखने वाले सावधान!

लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, यह तथ्य विगत कुछ वर्षों में किताबों में या भाषणों में दब कर रह गया था। अन्ना के आंदोलन में इसे फिर से लोकतंत्र के चेहरे पर चमक के रूप में फिर से स्थापित कर दिया है। संसद हो या विधानसभा, सासंद या विधायक। यह कहने की हिम्मत अब नहीं कर सकते कि वे चुने हुए प्रतिनिधि के नाते जो उचित समझेंगे, कहेंगे या करेंगे। अन्ना के आंदोलन में जनता को जेब में रखने वाले नेताओं को भरपूर आईना दिखा दिया है। जिस प्रधानमंत्री ने आंदोलन से पहले यह कहकर सबको चौंका दिया था कि सामाजिक क्षेत्र के स्थापित लोगों की जिद लोकतंत्र के लिये खतरा है। उसी प्रधानमंत्री ने बड़े ही दयनीय भाव से यह स्वीकार किया कि सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोग ही दरअसल लोकतंत्र के गहने हैं। सबक सिखाने से लेकर खुद सबक सीखने की प्रक्रिया में लोकतंत्र ने कई बार हिचकोले खाये। एक बार को ऐसा लगा कि जनता और सरकार के बीच जबरदस्त टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है और इस टकराव के कारण शायद 1975 की तरह देश शायद एक बार फिर आपातकाल की स्थिति में पहुंच जाये। सही मौके पर जनता के प्रतिनिधि होने की दुहाई देने वाले होश में आये और उन्होंने जनता के दवाब को समझा जाना और जनता के समर्थन में कानून बनाने की गंभीर कोशिश का आश्वासन दिया। अन्ना के आंदोलन का यह एक गुणकारी प्रभाव था। अन्ना के आंदोलन से एक बात और उभर कर सामने आयी और वह यह बात है कि आजादी के 65 साल बाद भी देश सचमुच लोकतंत्र की आस्था से जुड़ नहीं पाया है। कहने को जनता अपने मतों का अधिकार कर जनप्रतिनिधि चुनती है और जनप्रतिनिधि अपने विवेक का इस्तेमाल कर सरकार बनाते हैं और सरकारें अपने विवेक का इस्तेमाल कर कानून बनाती हैं। पर वास्तविकता लगातार दूर होती जा रही है। देश आजाद हुआ, केंद्र और राज्य में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो गया, थोड़े दिन तक सरकारें जनता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने की ईमानदार कोशिशें की लेकिन बाद के काल में जैसे–जैसे लोकतंत्र पर नेतातंत्र हावी हुआ, नेतातंत्र पर गुण्डातंत्र हावी हुआ और बाद में यही गुण्डातंत्र सफेद वस्त्र पहनकर अनैतिकता और भ्रष्टाचार के रूप में सामने आ खड़ा हुआ। वैसे–वैसे लोकतंत्र की आत्मा दुर्बल होती गयी और भारतीय गणतंत्र एक तरफ से गुणतंत्र बनकर रह गया। जहां कुछ लोग मिलकर देश को मनमाफिक तरीके से चलाने लगे, लूटपाट मचाने लगे और जनता को मालिक नहीं अपना नौकर समझने लगे। जाहिर है इस व्यवस्था में परिवर्तन अति अनिवार्य था और यह एक सामान्य तरीके से संभव नहीं था क्योंकि लोकतंत्र के पहरूये के रूप में जिन राजनीतिक दलों ने अपने आप को जनता के सामने पेश किया। उन सबमें लगभग समान दोष भर गये। ऐसा तंत्र हावी हुआ, भाई–भतीजावाद जोरों से चलने लगा और जनहित के बजाय स्वहित का पोषण मूलमंत्र बन गया। यह महसूस किया जाने लगा कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था शायद ही इन विकारों को दूर सकें इसीलिये किसी मसीहे की तलाश में भारतीय लोकतंत्र समाज की ओर टकटकी लगाये हुए था। कई सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी चले पर उनका अलग–अलग समय पर अलग–अलग प्रभाव रहा। पूरा देश एक सूत्र में पिरोने की क्षमता किसी सामाजिक आंदोलन में नहीं दिखी। लेकिन अन्ना के आंदोलन ने देश को एक नई करवट लेने पर मजबूर कर दिया। अन्ना सिर्फ प्रतीक थे, बदलाव के प्रतीक, जिजीविषा और अदम्य इच्छा लोगों के अन्दर कूट–कूट कर भरी थी। लोग वर्तमान व्यवस्था से पूरी तरह ऊब चुके थे। राजनैतिक पार्टियों की अर्कमण्यता और सरकार की निरंकुशता जनता को रोज–रोज मार रही थी इसीलिये अन्ना की चिंगारी ने इतना बड़ा मशाल जला दिया। आजादी के बाद देश फिर एक बार जगा। संसद और विधानसभा बौनी दिखाई देने लगी। लोगों की इच्छा और संकल्पशीलता भारी पड़ी। बदलाव की कहानी का प्राक्कथन लिखा जा चुका है। देखें इस पर किस तरह की इमारत खड़ी होती है।

चुनौतियों के आगे ढ़ेर नेतृत्व

अमरीका को देखिये, वहां पूर्ण आर्थिक महामन्दी है। अमरीकी अर्थव्यवस्था खुद चल रही है लेकिन वहां की सरकार जनता को आर्थिक मन्दी से उबारने के लिये हरसंभव प्रयास कर रही है। लोगों को एक या दो फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मिले रहे हैं। किसी भी तरीके से आर्थिक पहिया घुमाने में अमरीकी प्रशासन दिन–रात लगा हुआ है। एक हमारी अर्थव्यवस्था देखिये जैसे–जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है वैसे–वैसे सरकार अपनी आर्थिक नीति कठोर करती जा रही है।

■ विक्रम उपाध्याय

11 सितम्बर, को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पर हुए आतंकवादी हमले की दसवीं बरसी पर अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने वहां के नागरिकों के लिये एक संदेश जारी किया। उस संदेश में कहा गया कि अमरीका की पुलिस बहुत ही मजबूत और सजग पुलिस है. . . ठीक 4 दिन पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर एक बम विस्फोट हुआ और भारत के सुरक्षा अधिकारियों ने देश के सामने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा कि उन्हें आतंकवादी हमलों के बारे में खुफिया जानकारी होने के बावजूद हमले रोकने में कामयाबी नहीं मिली।

11 सितम्बर, को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पर हुए आतंकवादी हमले की दसवीं बरसी पर अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने वहां के नागरिकों के लिये एक संदेश जारी किया। उस संदेश में कहा गया कि अमरीका की पुलिस बहुत ही मजबूत और सजग पुलिस है। जिसने अपनी सतर्कता के बलबूते अमरीकी नागरिकों को दस साल तक सभी संभावित आतंकवादी हमलों से बचाये रखा। ठीक 4 दिन पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर एक बम विस्फोट हुआ और भारत के सुरक्षा अधिकारियों ने देश के सामने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा कि उन्हें आतंकवादी हमलों के बारे में खुफिया जानकारी होने के बावजूद हमले रोकने में कामयाबी नहीं मिली।

हम उनकी प्रशासन की तरह भारतीय प्रशासन में कभी भी देशवासियों को यह आश्वासन तक नहीं दिया कि उनकी पुलिस व्यवस्था दुरूस्त हो रही है और भविष्य में आतंकवादी हमलों को रोकने में कामयाब भी हो जायेंगे। इसके उलट भारतीय राजनीति में बहुत ऊँचे स्थान पर बिठाये जाने वाले कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी ने हमले के बाद कहा था कि आतंकवादियों को रोका नहीं जा सकता। हमारी स्थिति पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तो बेहतर है। इन दोनों की तथ्यों की तरफ पाठकों का ध्यान दिलाने के पीछे मकसद यह नहीं, जनता को यह बताना है कि हमारी कांग्रेस सरकार निकम्मी है और अमरीका में ओबामा की सरकार बहुत सुलझी हुई। इन दोनों तथ्यों की तरफ ध्यान दिलाने का सिर्फ एक मकसद यह जानना है कि क्या हमारा नेतृत्व चुनौतियों से पार पाने में

सक्षम है। इनके कंधे पर देश के नेतृत्व का भार है या जिन कंधों पर देश का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी रखने तमाम कवायदें हो रही हैं। क्या वे कंधे इसके काबिल हैं? सवाल किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि देश के पूरे राजनीतिक नेतृत्व को लेकर है। मामला सिर्फ आतंकवाद या आतंकवादी हमले तक सीमित नहीं, देश की तमाम चुनौतियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या हम सक्षम देश के अक्षम नेतृत्व की स्थिति में नहीं हैं। विश्लेषण एक–दो महीने का नहीं पिछले एक दशक का करें तो हमें लगेगा कि हमें सोफ्ट स्टेट के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। हमारी अपनी स्वतंत्र नीति होते हुए भी उनका अनुपालन हम विदेशी इशारों पर कर रहे हैं। चाहे आर्थिक मामला हो या सामरिक या फिर कूटनीतिक। हर जगह लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है पर जनता के सामने कुछ और परोसा जा रहा है।

पहले आर्थिक मामले की चर्चा करते हैं। लगातार पांच साल से देश महंगाई की मार झेल रहा है। आर्थिक विकास की गति 7.5–8 फीसदी तक प्राप्त करने का दावा करने वाली सरकार महंगाई के आंकड़े को कम करने में बुरी तरह फेल हुई है। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 10 फीसदी से ऊपर चल रही है। कभी तेल की मारामारी तो कभी चीनी का टोटा, कभी प्याज को लेकर किल्लत तो कभी अनाज के लिये रोना। सरकार टका सा जवाब देती है, प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक एक ही बात कहते हैं कि उनके पास जादू की छड़ी नहीं। भला उन्हें कौन बताये कि सत्ता के पटल पर उन्हें जनता ने जादू के खेल के लिये नहीं भेजा है। बल्कि अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने और आम जीवन सुलभ बनाने के एक इरादे से जनता ने उन्हें चुना है। लेकिन राजनैतिक नेतृत्व की बानगी देखिये, चीनी गोदाम में सड़ गयी लेकिन बाजार में सस्ती नहीं हुई, गेहूं की लाखों बोरियां बरसात में गल गयीं पर जनता भूखी रही। सुप्रीम कोर्ट तक को इस मामले में सरकार को प्रताड़ लगानी पड़ी पर राजनैतिक नेतृत्व को इसे लेकर कभी पछतावा नहीं हुआ। हर बार टका सा जवाब कि महंगाई अभी कम नहीं हो सकती। दूसरी तरफ अमरीका को देखिये, वहां पूर्ण आर्थिक महामन्दी है। अमरीकी अर्थव्यवस्था खुद चल रही है लेकिन वहां की सरकार जनता को आर्थिक मन्दी से उबारने के लिये हरसंभव प्रयास कर रही है। लोगों को एक या दो फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मिले रहे हैं। किसी भी तरीके से आर्थिक पहिया घुमाने में अमरीकी प्रशासन दिन–रात लगा हुआ है। एक हमारी अर्थव्यवस्था देखिये जैसे–जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है वैसे–वैसे

मामला सिर्फ आतंकवाद या आतंकवादी हमले तक सीमित नहीं, देश की तमाम चुनौतियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या हम सक्षम देश के अक्षम नेतृत्व की स्थिति में नहीं हैं। विश्लेषण एक–दो महीने का नहीं पिछले एक दशक का करें तो हमें लगेगा कि हमें सोफ्ट स्टेट के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। हमारी अपनी स्वतंत्र नीति होते हुए भी उनका अनुपालन हम विदेशी इशारों पर कर रहे हैं। चाहे आर्थिक मामला हो या सामरिक या फिर कूटनीतिक। हर जगह लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है पर जनता के सामने कुछ और परोसा जा रहा है।

सरकार अपनी आर्थिक नीति कठोर करती जा रही है। कर्ज की दर 6–7 फीसदी तक बढ़ाकर 14–15 फीसदी कर दी गयी है। न व्यापारियों को आर्थिक मदद मिल रही है, न उद्यमियों को। किसी भी उद्योग के लिये कोई विशेष पैकेज, योजना या रणनीति नहीं। क्या देश का नेतृत्व जनता को यूंही मंझधार में छोड़ देना चाहता है।

रिजर्व बैंक लगातार अपनी तिमाही मौद्रिक नीति में कर्ज की दर बढ़ाता जा रहा है। हमारी इस केंद्रीय बैंक की नीति है, कम पैसे होंगे तो कम सामान खरीदे जायेंगे और महंगाई की दर नीचे आ जायेगी। यानि औद्योगिक और निर्माण की गतिविधियां रोककर सरकार महंगाई पर अंकुश लगाना चाहती है। रणनीतिक मामले में देखिये एक तरफ अमरीका अपने ऊपर हुए एक हमले का जवाब कई देशों को नेस्तनाबूत करके भी देता है। दूसरी तरफ हम सैंकड़ों हमले खाने के बाद भी गीदड़ भभकी के आगे कुछ नहीं कर पाते। अभी हाल ही में खुलासा हुआ कि मुंबई हमले की योजना बनाने वाला रिचर्ड हेडली को देश में लाने के प्रति भारत सरकार कभी गंभीर ही नहीं रही। उसने अमरीकी प्रशासन को यहां तक कहा कि हेडली को भारत सौंपने की मांग सिर्फ जनता को छलावे में रखने के लिये कर रही है। भारतीय कूटनीतिज्ञ हर मोर्चे पर विफल और उनका नेतृत्व करने वाले नेता हर मामले पर एकचित्त। न तो उनके अंदर कोई व्यग्रता है, न उनके अंदर देश की इज्जत बनाये रखने के लिये परिपाटी को तोड़ने की ताकत। वे आज भी पाकिस्तान से बात करने को लेकर अमेरीका का मुंह तांकते हैं, हमले की तो बात ही क्या है।

सिर्फ आर्थिक और कूटनीतिक मामलों में ही क्यों। आंतरिक मामलों में भी हमारा देश कई बार नेतृत्वहीन लगता है। यह नेतृत्व की नाकामी ही है कि पिछले कई वर्षों से देश के खजाने में कुछ स्वार्थी तत्वों ने एक तरफ से सेंध लगा रखी है। एक–एक कर "चोर" बाहर निकलते जा रहे हैं और शोर मचने के बाद उनको सजा देने का स्वांग दिखाया जा रहा है। टूजी, थ्रीजी, कॉमनवेल्थ और आदर्श घोटालों के बाद भी लगातार भ्रष्टाचार की खबरें आती जा रही हैं। अभी हाल ही में सीएजी ने तेल मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बारे में तमाम अनियमितायें जनता के सामने रखीं हैं। लोग घोटाले की खबरें सुनते–सुनते तंग आ गये हैं लेकिन घोटाले की फेहरिस्त कम नहीं हो रही है। उसके बावजूद भी देश का नेतृत्व एक बार भी यह गंभीर कोशिश करता नहीं दिखाई दे रहा है कि वह भी सभी प्रकार के घोटालों से देश को ऊबारने के लिये उचित कानून या प्रकिया का पालन करने के लिये उत्सुक भी है। लगातार घोटालों पर पर्दा डालना, दोषियों को एक सीमा से अधिक जाकर संरक्षण प्रदान करना और पूरी व्यवस्था को सड़ने देना नेतृत्व की मजबूरी नहीं हो सकती। ❑

एक तरफ अमरीका अपने ऊपर हुए एक हमले का जवाब कई देशों को नेस्तनाबूत करके भी देता है। दूसरी तरफ हम सैंकड़ों हमले खाने के बाद भी गीदड़ भभकी के आगे कुछ नहीं कर पाते। अभी हाल ही में खुलासा हुआ कि मुंबई हमले की योजना बनाने वाला रिचर्ड हेडली को देश में लाने के प्रति भारत सरकार कभी गंभीर ही नहीं रही। उसने अमरीकी प्रशासन को यहां तक कहा कि हेडली को भारत सौंपने की मांग सिर्फ जनता को छलावे में रखने के लिये कर रही है। भारतीय कूटनीतिज्ञ हर मोर्चे पर विफल और उनका नेतृत्व करने वाले नेता हर मामले पर एकचित्त।

नए संघर्ष की शुरूआत

संसद के विशेष सत्र में सर्वानुमति से पारित प्रस्ताव और उसके परिणामस्वरूप अन्ना के 12 दिन पुराने अनशन का टूटना वास्तव में देश को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और सुशासन देने की परिणति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उपरोक्त घटनाओं से सिद्ध होता है कि सत्ता अधिष्ठान का बदला रवैया उसके हृदय परिवर्तन का नहीं, बल्कि एक रणनीति का हिस्सा था। यह तो संघर्ष का आरंभ है, अंत नहीं। स्वच्छ भारत के लिए वास्तविक समर तो अभी शेष है।

■ बलवीर पुंज

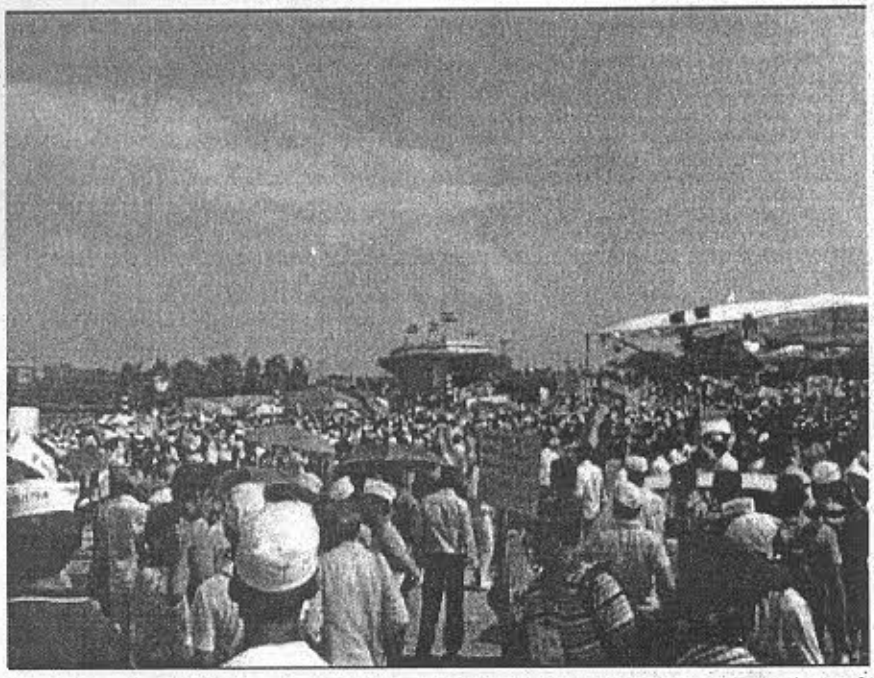

अंततः जननायक अन्ना हजारे और उनके साथ जुड़े करोड़ों भारतीयों के प्रबल समर्थन के कारण कांग्रेसनीत संप्रग सरकार को अपनी अधिनायकवादी मानसिकता त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार अन्ना हजारे द्वारा जनभावनाओं के अनुरूप सुझाए गए तीन बिंदुओं–जनशिकायत व सिटिजन चार्टर, राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति और निचले स्तर की नौकरशाही को लोकपाल कानून के दायरे में लाने पर सहमत हो गई है। भारतीय जनतंत्र में यह जन की तंत्र पर निश्चित विजय है।

लोकपाल संस्था के निर्माण का रास्ता भले साफ हो गया हो, किंतु संप्रग–2 के रहते क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं? अभी हाल की ही तीन घटनाएं लीजिए। वामपंथी दलों द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण 22 जुलाई, 2008 को सरकार को सदन में विश्वास मत हासिल करना था। तब भाजपा के तीन सांसदों–अशोक अर्गल, फगन सिंह कुलस्ते और महावीर भगोरा ने सदन में नोटों की गड्डियां दिखाते हुए नोट फोर वोट कांड का खुलासा किया था। विपक्षी दलों के दबाव में मामले की जांच के लिए कृष्णचंद्र देव समिति गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट में सांसदों को घूस दिए जाने को झूठा बताया।

यह विषय दिल्ली पुलिस के पास जांच के लिए आया, किंतु पिछले तीन साल से इस दिशा में कुछ नहीं किया गया। हाल में न्यायालय का चाबुक पड़ने के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई, किंतु इससे सत्ता में होते हुए कांग्रेस द्वारा संवैधानिक निकायों के दुरुपयोग की पुष्टि भी हुई है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें ही आरोपी बना दिया गया। इस कांड का खुलासा

सरकार और अन्ना के बीच कायम गतिरोध तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा अन्ना हजारे को दिए गए आश्वासन के बाद सरकार का पलटना और उसके बाद संसद में कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी के भाषण के बाद स्पष्ट हो गया था कि एक सशक्त लोकपाल बिल लाने के लिए सरकार गंभीर नहीं है और वह मामले को लटकाने की फिराक में है। जनाक्रोश जब संसद की देहरी तक जा पहुंचा तो सरकार अपना हठ त्याग कर जनलोकपाल बिल पर चर्चा कराने को तैयार हुई. . .

करने में अहम भूमिका निभाने वाले सुधींद्र कुलकर्णी को भी कठघरे में खड़ा किया गया है। वोट के लिए नोट के सूत्रधार अमर सिंह तो मुखौटा मात्र हैं। इसके असली लाभार्थियों के बारे में दिल्ली पुलिस खामोश है। नोट के बदले वोट संप्रग सरकार बचाने के लिए था। फिर सरकार पापमुक्त कैसे हो गई? ऐसे तंत्र पर जनता का विश्वास कैसे रहे? अपने क्षुद्र राजनीतिक लाभों के लिए संवैधानिक निकायों के दुरुपयोग का नवीनतम उदाहरण आंध्र प्रदेश और गुजरात से है।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी के पुत्र जगनमोहन रेड्डी ने जब से कांग्रेस से किनारा कर अलग पार्टी बनाई है, वह कांग्रेस की आंखों में चुभ रहे हैं। कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी को कानूनी शिकंजे में कसने की फिराक में है। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में वाईएसआर रेड्डी और जगनमोहन रेड्डी पर बेनामी संपत्ति जमा करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। यदि कांग्रेस भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रति इतनी गंभीर है तो उसने दूसरी बार जनादेश मिलने के बाद वाईएसआर रेड्डी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? इसके विपरीत हमारे सामने देश के सबसे बड़े कर चोर हसन अली का उदाहरण है। वर्षों पूर्व आयकर और प्रवर्तन निदेशालय को हसन अली के कारनामों की भनक लग चुकी थी, किंतु राजनीतिक आकाओं ने उसका बाल भी बांका नहीं होने दिया। भाजपा शासित गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति कांग्रेसी अधिनायकवाद का ज्वलंत उदाहरण है। गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल ने विगत 25 अगस्त को राज्य सरकार की अनदेखी करते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरए मेहता को गुजरात का लोकायुक्त नियुक्त कर दिया। गुजरात लोकायुक्त अधिनियम, 1986 के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति से पहले गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष से मंत्रणा के बाद सरकार मंत्रिमंडल से प्रस्तावित लोकायुक्त का नाम राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजती है। बेनीवाल ने इस पूरी प्रक्रिया की अनदेखी की है। गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति सन 2006 से ही लटकी हुई है। सरकार ने तब सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्षितिज आर व्यास को लोकायुक्त के लिए नामित किया था। इस पर आपत्ति करते हुए कांग्रेस ने बैठक का बहिष्कार किया था। बाद में स्वयं कांग्रेस शासित महाराष्ट्र में व्यास को महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया।

पिछले कुछ समय से बड़े–बड़े घोटालों के प्रति सरकार की उदासीनता और सत्ता के शिखर स्तर पर तटस्थता के भाव से जनता ऊब चुकी थी। सार्वजनिक धन की लूट पर सीएजी और पीएसी की रिपोर्ट को सरकार ने मानने से इंकार किया। घोटालों का खुलासा करने वाले मीडिया को उसकी कथित अति सक्रियता के लिए लताड़ा गया। विदेशों में जमा काले धन की वापसी को लेकर आंदोलन करने वाले स्वामी रामदेव का पुलिसिया जुल्म के बल पर दमन किया गया।

स्पष्ट है कि व्यास से कांग्रेस का कोई वैचारिक मतभेद नहीं था। वह इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रही थी। कांग्रेस जनतांत्रिक पार्टी होने का दावा तो करती है, किंतु उसका आचरण अधिनायकवादी और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। अन्ना हजारे के अनशन के दौरान कांग्रेस का निकृष्ट चेहरा जनता के सामने उजागर हुआ। पी. चिदंबरम, कपिल

सिब्बल, सलमान खुर्शीद, वीरप्पा मोइली, मनीष तिवारी जैसे वकीलों की टीम भारी पड़ रही है, जो जनतांत्रिक व राजनीतिक समस्याओं को केवल कानूनी चाबुक से सुलझाना चाहते हैं।

सरकार और अन्ना के बीच कायम गतिरोध तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा अन्ना हजारे को दिए गए आश्वासन के बाद सरकार का पलटना और उसके बाद संसद में कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी के भाषण के बाद स्पष्ट हो गया था कि एक सशक्त लोकपाल बिल लाने के लिए सरकार गंभीर नहीं है और वह मामले को लटकाने की फिराक में है।

जनाक्रोश जब संसद की देहरी तक जा पहुंचा तो सरकार अपना हठ त्याग कर जनलोकपाल बिल पर चर्चा कराने को तैयार हुई, किंतु वह इस पर मतदान कराने को राजी नहीं हुई।

लोकपाल बिल पिछले 42 सालों से लंबित है और इसे संसद में विचार के लिए नौ बार पेश किया जा चुका है। राजनीतिक

लोकपाल बिल पिछले 42 सालों से लंबित है और इसे संसद में विचार के लिए नौ बार पेश किया जा चुका है। राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में यह अब तक अधर में लटका हुआ था।

इच्छाशक्ति के अभाव में यह अब तक अधर में लटका हुआ था।

पिछले कुछ समय से बड़े–बड़े घोटालों के प्रति सरकार की उदासीनता और सत्ता के शिखर स्तर पर तटस्थता के भाव से जनता ऊब चुकी थी। सार्वजनिक धन की लूट पर सीएजी और पीएसी की रिपोर्ट को सरकार ने मानने से इंकार किया। घोटालों का खुलासा करने वाले मीडिया को उसकी कथित अति सक्रियता के लिए लताड़ा गया।

विदेशों में जमा काले धन की वापसी को लेकर आंदोलन करने वाले स्वामी रामदेव का पुलिसिया जुल्म के बल पर दमन किया गया। अन्ना हजारे की गिरफ्तारी के बाद जनता का सब्र टूट गया। हद तो तब हो गई, जब संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने इन आंदोलनों के पीछे विदेशी तत्वों का हाथ साबित करने की कोशिश की।

बीते माह को संसद के विशेष सत्र में सर्वानुमति से पारित प्रस्ताव और उसके परिणामस्वरूप अन्ना के 12 दिन पुराने अनशन का टूटना वास्तव में देश को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और सुशासन देने की परिणति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उपरोक्त घटनाओं से सिद्ध होता है कि सत्ता अधिष्ठान का बदला रवैया उसके हृदय परिवर्तन का नहीं, बल्कि एक रणनीति का हिस्सा था। यह तो संघर्ष का आरंभ है, अंत नहीं। स्वच्छ भारत के लिए वास्तविक समर तो अभी शेष है। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

देश की जनता जाग चुकी है

लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है और यही बात तो अन्ना हजारे जनता को बता रहे हैं। वे संसदीय व्यवस्था के शुद्धिकरण के लिए आवाज उठा रहे हैं और आम आदमी के प्रति संसद और राजनेताओं की जवाबदेही की याद दिला रहे हैं। यह उनका ही प्रताप है कि ऐसा विशाल आंदोलन अहिंसक रहा और सरकार विरोधी तेवर के बावजूद विपक्षी पार्टियां अपने फायदे में इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब लोकपाल कानून चाहे जब बने, अन्ना का यह आंदोलन तो सफल हो चुका है।

■ निरंकार सिंह

देश की जनता के भारी दबाव के बाद संसद ने जनलोकपाल बिल की तीन प्रमुख मांगों के समर्थन में सशर्त प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब यह प्रस्ताव स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। सरकार स्थायी समिति का इस्तेमाल कभी–कभी एक हथियार के रूप में भी करती है। इसलिए जनलोकपाल की जंग अभी अधूरी है। जो काम सरकार को खुद करना चाहिए था, उसके लिए अन्ना हजारे को 12 दिन तक भूख हड़ताल करनी पड़ी और पूरे देश की जनता को सड़कों पर उतरना पड़ा।

इस दौरान कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के बीच जो सियासी खेल हुआ, उसे भी पूरे देश ने देखा। कपिल सिब्बल, पी चिदंबरम, सलमान खुर्शीद, प्रणब मुखर्जी के बाद राहुल गांधी ने जहां नए लोकपाल बिल का सुझाव देकर पूरी बाजी को पलटने की असफल कोशिश की, वहीं भाजपा ने जनलोकपाल बिल की प्रमुख मांगों को कुछ शर्तों के साथ खुला समर्थन देकर बढ़त हासिल कर ली है।

अन्ना के अनशन और जनलोकपाल बिल को दिल्ली के रामलीला मैदान और देश–विदेश में जिस तरह का व्यापक समर्थन मिला, उससे संप्रग सरकार और अन्य राजनीतिक दलों की आंखें खुल जानी चाहिए। जन आंदोलनों को नकार कर कोई भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं चलाई जा सकती है। अन्ना को मिले समर्थन से राजनीतिक दलों के होश उड़ गए हैं। उनका राजनीतिक जनाधार खिसक गया है और इससे सभी दल बेचैन हैं।

पिछले कुछ दिनों के दौरान जनता ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के रंग बदलते चेहरों को देखा है। राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ जनता में इतना गुस्सा क्यों है? इस बात को समझने के बजाय वे अब संसद की सर्वोच्चता की दलील देकर अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करते हैं, पर लोकशाही का मतलब क्या है? क्या हम सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं या जनता के हाथ में सौंपना चाहते हैं? यदि हम लोगों का

पिछले कुछ दिनों के दौरान जनता ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के रंग बदलते चेहरों को देखा है। राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ जनता में इतना गुस्सा क्यों है? इस बात को समझने के बजाय वे अब संसद की सर्वोच्चता की दलील देकर अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करते हैं, पर लोकशाही का मतलब क्या है? क्या हम सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं या जनता के हाथ में सौंपना चाहते हैं?

शासन, लोगों का राज्य लाना चाहते हैं तो हमारे कार्य की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? पिछले लगभग पांच दशक में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अगर हम अपनी संसद से एक लोकपाल विधेयक को भी पास नहीं करा सके तो हमारी नीति और नीयत पर जनता को संदेह क्यों नहीं होना चाहिए।

संसद की सर्वोच्चता क्या भ्रष्टाचार और लूट को रोकने में बाधक है? यह सवाल आज देश की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से पूछ रही है? सत्तारूढ़ संप्रग को सत्ता में आए सात साल से अधिक समय हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए इन सालों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पार्टी के नेताओं ने क्या कदम उठाए?

कांग्रेस पार्टी के जो नेता अब लोकपाल को चुनाव आयोग की तरह संवैधानिक दर्जा दिए जाने की वकालत कर रहे हैं, वे अब तक खामोश क्यों थे? वे किस बात का इंतजार कर रहे थे? अन्ना के आंदोलन से मुंह चुरा रही कांग्रेस अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस कथन को क्यों भूल गई कि आम आदमी के विकास के लिए केंद्र से चला एक रुपये का 15 पैसा ही उसके पास तक पहुंचता है। बाकी 85 पैसा दलालों और भ्रष्टाचारियों

के पास पहुंच जाता है।

अन्ना हजारे उसी संकट से निपटने के लिए पिछले दशकों से अलख जगा रहे हैं। अब उसे संसद की सर्वोच्चता के नाम पर लटका कर राजनीतिक दल साबित क्या करना चाहते हैं। अपने वेतन, भत्तों और सांसद निधि को बढ़ाए जाने वाले बिलों को पास कराने में दो मिनट से भी ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन जनलोकपाल बिल के लिए तमाम कायदे-कानून बताए जा रहे हैं। जहां उनका स्वार्थ सिद्ध होता है, वहां संसद की सर्वोच्चता का कोई सवाल नहीं उठता है।

कांग्रेस पार्टी के जो नेता अब लोकपाल को चुनाव आयोग की तरह संवैधानिक दर्जा दिए जाने की वकालत कर रहे हैं, वे अब तक खामोश क्यों थे? वे किस बात का इंतजार कर रहे थे? अन्ना के आंदोलन से मुंह चुरा रही कांग्रेस अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस कथन को क्यों भूल गई कि आम आदमी के विकास के लिए केंद्र से चला एक रुपये का 15 पैसा ही उसके पास तक पहुंचता है। बाकी 85 पैसा दलालों और भ्रष्टाचारियों के पास पहुंच जाता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध करार दिए जाने के बाद जिस तरह 25-26 दिसंबर 1975 को रातोंरात इमरजेंसी लगाई गई तो क्या उस समय संसद की सर्वोच्चता का ध्यान रखा गया था? नागरिक अधिकारों की बहाली के लिए जनता को ही संघर्ष करना पड़ा था।

बाद में जब 1977 में चुनाव हुए तो उत्तर भारत में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गईं। लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च मानी गई है, क्योंकि वह जनता की आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रतीक मानी जाती है। उसे यह अधिकार देश की जनता ने ही दिया है।

अन्ना हजारे आज इस देश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रतीक बन गए हैं। उनका कोई निजी एजेंडा नहीं है। वह जनहित में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार की उन गंभीर समस्याओं को उठाया है, जिससे आज इस देश की आम जनता त्रस्त है। वह

अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। वह चाहते हैं कि केंद्र की पूरी नौकरशाही लोकपाल के दायरे में लाई जाए। राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति अनिवार्य की जाए।

सिटीजन चार्टर यानी सरकारी दफ्तरों के लिए संहिता बनाई जाए, जिससे आवेदनों का एक समय–सीमा में निपटारा हो। लोकपाल की नियुक्ति निष्पक्ष तरीके से हो और सीबीआइ की भ्रष्टाचार निवारण शाखा को उसके अधीन किया जाए। इसमें अनुचित कुछ नहीं है। इस काम को तो सरकार को खुद करना चाहिए, लेकिन इसके लिए यदि अन्ना को अनशन करना पड़े और पूरे देश को सड़क पर उतरना पड़े तो संसद को जनआकांक्षाओं का प्रतीक और न्याय का मंदिर कैसे कहा जा सकता है।

लोकपाल के बाद अन्ना का दूसरा मुद्दा चुनाव सुधार का है। आज संसद के 150 से अधिक सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। जनता के लिए कानून बनाने वाले खुद कानून के कठघरे में है। ऐसे में उनसे यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वे जनता के लिए बेहतर कानून बनाएंगे? अन्ना ने अपने आंदोलन को दूसरी आजादी का संघर्ष बनाया है और इसकी शुरुआत हो चुकी है।

लोकपाल के बाद अन्ना का दूसरा मुद्दा चुनाव सुधार का है। आज संसद के 150 से अधिक सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। जनता के लिए कानून बनाने वाले खुद कानून के कठघरे में है। ऐसे में उनसे यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वे जनता के लिए बेहतर कानून बनाएंगे? अन्ना ने अपने आंदोलन को दूसरी आजादी का संघर्ष बनाया है और इसकी शुरुआत हो चुकी है।

लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है और यही बात तो अन्ना हजारे जनता को बता रहे हैं। वे संसदीय व्यवस्था के शुद्धिकरण के लिए आवाज उठा रहे हैं और आम आदमी के प्रति संसद और राजनेताओं की जवाबदेही की याद दिला रहे हैं। यह उनका ही प्रताप है कि ऐसा विशाल आंदोलन अहिंसक रहा और सरकार विरोधी तेवर के बावजूद विपक्षी पार्टियां अपने फायदे में इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब लोकपाल कानून चाहे जब बने, अन्ना का यह आंदोलन तो सफल हो चुका है। आज कांग्रेस और भाजपा के कुछ सांसदों ने अगर अपने ही दलीय अनुशासन के खिलाफ जाने की हिमाकत दिखाई है तो यह इसलिए कि जनता से लगातार कटते जाने के खतरे को कुछ नेता अब समझने को तैयार हैं।

पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम में जनता का गुस्सा हर दल और उसके सांसदों के प्रति दिखा है। यह गुस्सा इसलिए है कि लोकतंत्र को देश में एक दिन के चुनावी अनुष्ठान तक सीमित कर दिया गया है। लोकसंवाद की सतत प्रक्रिया पांच साल की मुंहजोरी के लिए मजबूर हो गई है। एक सफल लोकतंत्र जीवंत और प्रगतिशील भी होता है। समय और अनुभव के साथ उसमें संशोधन जरूरी है।

जनलोकपाल अगर आज की तारीख में जनता का बड़ा मुद्दा है तो इसके बाद सबसे जरूरी मुद्दा दलीय राजनीति के ढांचे और चुनाव प्रणाली में सुधार है। जनता इस लोकतंत्र की प्रहरी बने तथा नीचे के कर्मचारी से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक, सबके कामकाज पर निगरानी रखें।

ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो कि जनता की इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ भी न कर सके। इसके लिए जनता को निरंतर जागरूक और सावधान रहना है। इसके बिना स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। मात्र मतदान कर देने से कर्तव्य पूरा हो गया, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अन्ना की दूसरी आजादी में तो लोकतंत्र के एक सर्वथा नए स्वरूप की कल्पना है।

जब लोग समाज–जीवन के कार्यों में प्रत्यक्ष हिस्सा ले सकें और तंत्र लोक की अनुमति और सहमति से काम करता हो, सच्चा लोकतंत्र तभी संभव होगा। इसके लिए लोक चेतना जागृत रखनी होगी। महात्मा गांधी ने कहा था कि इस तंत्र का केवल यह अर्थ नहीं कि जनता के मत से शासन स्थापित हुआ, बल्कि यह भी कि जनता में ऐसी क्षमता भी हो कि शासकों के नालायक पाए जाने पर उन्हें पद से हटा भी सके।

अन्ना कहते हैं कि चुनाव में नापसंदगी का भी कॉलम होना चाहिए। यदि नापसंदगी को ज्यादा वोट मिले तो वहां फिर से चुनाव होना चाहिए। ❑

चीन का राजनीतिक हथियार

एशिया की धुरी चीन में ऐसी नदियों की संख्या पूरे विश्व में सबसे अधिक है जो चीन से निकलकर अन्य देशों में बहती हैं। ये नदियां रूस, भारत, कजाकिस्तान आदि देशों से होकर गुजरती हैं। ऐसी तमाम बड़ी नदियां उन क्षेत्रों से निकली हैं, जिन पर चीन ने जबरन कब्जा किया है और जो चीन के भूभाग का 60 प्रतिशत क्षेत्र है। इस शक्तिशाली जल संसाधन के संबंध में जल बंटवारे की व्यवस्था या फिर अन्य सहयोगी संस्थागत तंत्र विकसित करने के तमाम प्रयास विफल साबित हुए हैं।

■ ब्रह्मा चेलानी

चीन ने दुर्लभ खनिजों के एकाधिकार को व्यापारिक लाभ के हथियार के रूप में इस्तेमाल करके और दक्षिण चीन सागर में सीमा विवाद पर बहुपक्षीय प्रयासों से पहले ही दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। अब उसने पानी को संभावित राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर अपने पड़ोसी देशों को गहरी चिंता में डाल दिया है।

एशिया की धुरी चीन में ऐसी नदियों की संख्या पूरे विश्व में सबसे अधिक है जो चीन से निकलकर अन्य देशों में बहती हैं। ये नदियां रूस, भारत, कजाकिस्तान आदि देशों से होकर गुजरती हैं। ऐसी तमाम बड़ी नदियां उन क्षेत्रों से निकली हैं, जिन पर चीन ने जबरन कब्जा किया है और जो चीन के भूभाग का 60 प्रतिशत क्षेत्र है। इस शक्तिशाली जल संसाधन के संबंध में जल बंटवारे की व्यवस्था या फिर अन्य सहयोगी संस्थागत तंत्र विकसित करने के तमाम प्रयास विफल साबित हुए हैं।

वास्तव में, जैसा कि बांधों के निर्माण से संकेत मिलता है, चीन अपने फायदे के लिए उलटी धारा में तैर रहा है। मेकोंग, सलवीन, ब्रह्मपुत्र, अरुण, इरटिश इली और अमुर जैसी नदियों पर चीन बड़े–बड़े बांध बना रहा है। यह सब उन देशों की चिंताओं को दरकिनार करके किया जा रहा है, जहां से होकर नदियां गुजरती हैं। दुनिया के किसी भी देश में इतने बांध नहीं हैं जितने चीन में। इनमें विश्व का सबसे बड़ा बांध थ्री जॉर्जेस भी शामिल है।

विश्व के 50 हजार बड़े बांधों के करीब आधे बांध चीन में ही हैं। इसके बावजूद बांधों के साथ अपनी दीवानगी

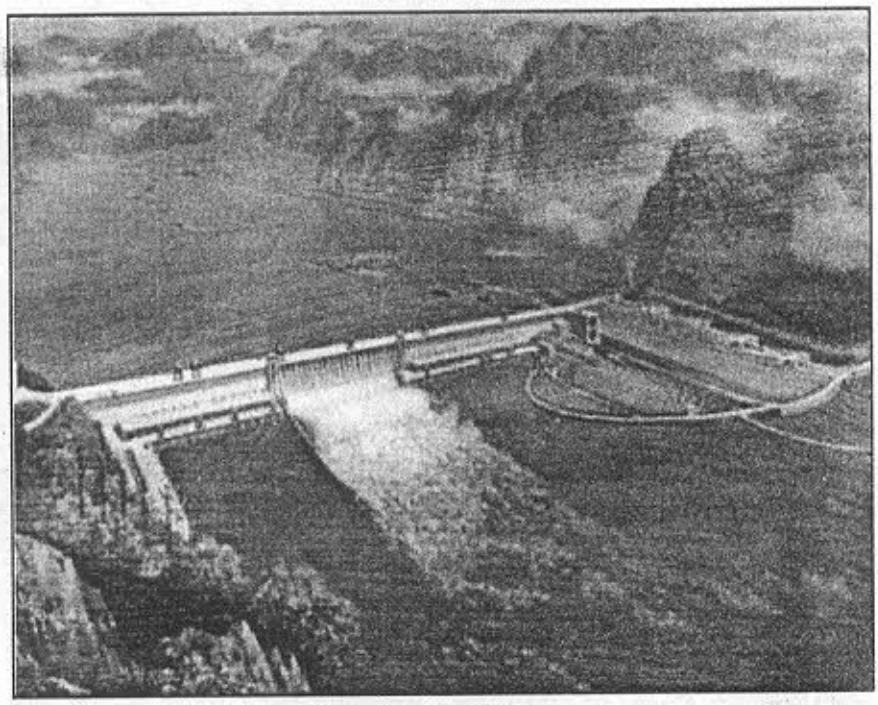

वास्तव में, जैसा कि बांधों के निर्माण से संकेत मिलता है, चीन अपने फायदे के लिए उलटी धारा में तैर रहा है। मेकोंग, सलवीन, ब्रह्मपुत्र, अरुण, इरटिश इली और अमुर जैसी नदियों पर चीन बड़े–बड़े बांध बना रहा है। यह सब उन देशों की चिंताओं को दरकिनार करके किया जा रहा है, जहां से होकर नदियां गुजरती हैं। दुनिया के किसी भी देश में इतने बांध नहीं हैं जितने चीन में। इनमें विश्व का सबसे बड़ा बांध थी जॉर्जेस भी शामिल है।

कम करने के बजाय चीन ने नदियों का प्रवाह बदलने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। इस प्रकार चीन अंतरराष्ट्रीय नदियों का स्वरूप बदलकर उन्हें राष्ट्रीय बनाने में जुटा है। मेकोंग नदी पर चीन का नवीनतम बांध पेरिस के एफिल टॉवर से भी ऊंचा है। यह अकेला बांध इतनी ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है, जितना इस नदी पर बांध बनाकर अन्य तमाम देश कर रहे हैं। इसी प्रकार 5,850 मेगावाट की विद्युत क्षमता वाला निर्माणाधीन नूओझाडु बांध ऊंचाई में तो मेकोंग बांध जितना नहीं होगा, किंतु क्षमता में उससे बड़ा होगा।

पिछली गर्मियों में, चीन के सरकारी पनबिजली उद्योग ने एक नक्शा जारी किया था, जिसमें निर्माण के लिए स्वीकृत प्रमुख नए बांधों की सूची थी। इनमें ब्रह्मपुत्र पर मेटोग (चीन में मोतुओ) पर बनने वाले बांध का भी जिक्र था। यह बांध चीन में स्थित विश्व के सबसे बड़े 18,300 मेगावाट के थ्री जोर्जेस बांध से भी दोगुना होगा। मेटोग भारत सीमा पर विवादित क्षेत्र में आता है।

अंतरराष्ट्रीय आकलनों के अनुसार अगले एक दशक में विकसित देशों में बांधों की संख्या स्थिर रहने का अनुमान है, जबकि विकासशील देशों में बनने वाले बांधों में आधे से अधिक चीन में होंगे। बांधों के निर्माण को लेकर इस अतिउत्तेजना के दुष्परिणाम पहले ही नजर आने लगे हैं। पहला तो यह कि चीन अपने अधिकांश पड़ोसी देशों के साथ जल विवाद में उलझा हुआ है। इनमें रूस और भारत जैसे बड़े देशों से लेकर उत्तर कोरिया और म्यांमार जैसे छोटे देश भी शामिल हैं।

दूसरे, परंपरागत आबादी वाले क्षेत्रों में विशाल बांधों के निर्माण के कारण तिब्बत, जिनजियांग और इनर मंगोलिया जैसे क्षेत्रों में चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह या विरोध का विस्फोट हो गया है। तीसरा दुष्परिणाम यह है कि इन परियोजनाओं के कारण अंतरराष्ट्रीय नदियों के चीन की आंतरिक नदियों में तब्दील होने का खतरा पैदा हो गया है।

देश में ही नहीं, चीन विदेशों में भी बांध बनाने वाले देशों में अग्रणी है। पाक अधिकृत कश्मीर से लेकर म्यांमार के समस्याग्रस्त कचिन और शान प्रांतों में भी चीन बांध बनाकर विवादों को हवा दे रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित–बाल्टिस्तान क्षेत्रों में चीनी सेना की इकाइयां बांध निर्माण कर भारत की चिंताओं को बढ़ा रही हैं तो म्यांमार में चीन द्वारा बांध निर्माण के कारण कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी और सरकार के बीच 17 साल से चला आ रहा युद्धविराम फिर से खूनी संघर्ष में बदल गया है।

चीनी नदियों के साझीदार देश पनबिजली परियोजनाओं पर गोपनीयता के आवरण से चिंतित हैं। इनका निर्माण चुपचाप, लगभग गोपनीय रूप से किया जाता है और फिर इन्हें बाढ़ नियंत्रण के लिए जरूरी बताकर अपरिवर्तनीय घोषित कर दिया जाता है।

इससे भी बदतर स्थिति यह है कि चीन अपने किसी पड़ोसी देश के साथ जन–बंटवारे पर कोई संधि करने का इच्छुक नहीं है। जल बंटवारा, साझा जल संसाधन, जल संधि, सामान्य मानक और नियम जैसी शब्दावली चीन के लिए अभिशाप है। चीन उन तीन देशों में से एक है जिन्होंने 1997 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय जल नीति पर साझा संसाधन के प्रस्ताव का विरोध किया था।

किसी दुर्घटनावश ऐसा नहीं है कि दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया के सभी साझा नदियों वाले देशों के बीच जल संधियां हैं, किंतु चीन की अपने किसी पड़ोसी के साथ ऐसी संधि नहीं है। सभी प्रमुख एशियाई नदियों के गले को दबाने वाला चीन एक उभरती हुई महाशक्ति है। वह अपनी दबंगई का खुला प्रदर्शन कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही हैं। इस परिप्रेक्ष्य में चीन एशिया में एकमात्र बड़ी बाधा है जो साझा नदियों पर संस्थागत सहयोग और परस्पर व टिकाऊ लाभ के लिए किसी भी प्रकार की संधियों के पक्ष में हैं।

असल में सबसे अधिक आबादी वाले एशिया में पानी विभिन्न देशों के बीच बढ़ते मतभेद और मनमुटाव के श्चोत के रूप में उभर रहा है। एशिया की प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। पानी की बढ़ती तंगी से एशिया के तेजी से बढ़ते आर्थिक विकास पर ग्रहण लग सकता है। निवेशकों के लिए इसका खतरा गैरविकास ऋण, रियल एस्टेट बुलबुला और राजनीतिक भ्रष्टाचार से कम घातक नहीं है। इस खतरे के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। जल नक्शे पर एशिया का केंद्रीय भाग होने के नाते बीजिंग पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाना चाहिए कि वह पड़ोसी देशों के हितों को प्रभावित न करे और साझा जल के मनमाने इस्तेमाल से बाज आए।

उसे संस्थागत जल सहयोग को स्वीकार करना चाहिए, जो सभी पार्टियों के बीच संयम की मांग करता है ताकि कोई भी देश प्रभावित देश को नुकसान पहुंचा कर साझा जल का अनुचित इस्तेमाल न कर सके। ❑

बाढ़ ग्रस्त ग्रामीणों इलाकों की पीड़ा

अनेक गांवों में रोजी–रोटी की बिगड़ती स्थिति बाढ़ के बदलते रूप से जुड़ी हुई है। अनेक गांववासियों ने हमें बताया कि पहले बाढ़ आती थी और शीघ्र ही चली जाती थी पर अब बाढ़ और जल जमाव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। इस तरह एक ओर खरीफ की फसल नष्ट होती है तो दूसरी ओर रबी की फसल की समय पर बुवाई नहीं हो पाती। नदी और तटबंध के बीच फंसे गांवों की बिगड़ती समस्याओं को प्रायः स्वीकार कर लिया जाता है, पर साथ ही यह कहा जाता है कि जो लोग तटबंधों द्वारा बाढ़ से सुरक्षित किए गए हैं, उनकी संख्या कहीं अधिक है। पर इस बारे में सवाल उठना जरूरी है कि यह सुरक्षा कितनी वास्तविक है।

■ भारत डोगरा

बाढ़ और कटान से प्रभावित अनेक गांवों के लोग एक दीर्घकालीन संकट से गुजर रहे हैं। इन गांवों में गरीबी, अभाव और पलायन बढ़ रहे हैं। यह सच है कि

सरकार की विभिन्न रोजगार व पेंशन जैसी योजनाओं से उन्हें कुछ राहत भी मिलती है। इसके अतिरिक्त कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं ने इन गांवों में अच्छा कार्य कर लोगों का दुख–दर्द कम किया है पर इसके बावजूद लोगों की आजीविका का इतना नुकसान हुआ है उनकी स्थिति पहले से कहीं ज्यादा खराब है।

यह विशेषकर उन गांवों से स्पष्ट नजर आता है जो नदियों और तटबंधों के बीच फंसे हुए हैं। ऐसा ही एक गांव है गोरखपुर जिला का बंजारहा। लगभग 122 परिवारों का यह गांव राप्ती व रोहिणी के पास स्थित है। नदी व तटबंध के बीच फंसने के बाद अब यहां के लोगों को बाढ़ का प्रकोप पहले से कहीं अधिक सहना पड़ता है।

कुछ परिवारों को मुख्य रूप से अपने ही खर्च पर तटबंध के दूसरे पार बसना पड़ा है। यहां के एक बुजुर्ग ने तटबंध बनने से पहले के पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि उन दिनों गांव कहीं अधिक खुशहाल था। विशेषकर खाद्य उत्पादन व पोषण के बारे में गांव की स्थिति आज से कहीं बेहतर थी।

उन्होंने उस समय की विविधता भरी खेती के बारे में बताया कि गांव में बहुत–सी फसलें पनपती थीं। जैसे गेंहू, धान, कोदो, अरहर, बाजरा, मक्का, सावां, टांगुन, परवल, खरबूजा, कद्दू, शकरकंदी, धनिया, मैथी, चना, अजवायन, जौ, मटर, टमाटर व अनेक अन्य सब्जियां। विशेषकर टमाटर की खेती के लिए तो यह गांव मशहूर रहा है। इस विविधता भरी खेती के आधार पर यहां पशुपालन भी खूब पनपता था। पर अब कृषि व पशुपालन दोनों की संभावनाएं बहुत सिमट गई हैं।

जब तटबंध टूट जाते हैं तो इससे सुरक्षित किए गए गांवों में जो क्षति होती है वह सामान्य बाढ़ से कहीं अधिक होती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2010 की बाढ़ में तटबंध टूटने से गोंडा जिले की रदौली पंचायत में जो विनाशलीला हुई वह सामान्य बाढ़ से कहीं अधिक भयानक थी।

जो गांव तटबंध व नदी में फंसने के कारण बहुत सी कठिनाइयां पहले से झेल रहे हैं उनके प्रति विशेष सहायता व रक्षा का व्यवहार किया जाए। तटबंध बनाते समय उम्मीद की जाती है कि जो लोग तटबंध व नदी के बीच फंसेंगे उससे कहीं अधिक संख्या में लोगों को तटबंधों से सुरक्षा मिलेगी। किंतु जब तटबंध टूट जाते हैं तो इससे सुरक्षित किए गए गांवों में जो क्षति होती है वह सामान्य बाढ़ से कहीं अधिक होती है।

लगभग हर वर्ष बाढ़ के बावजूद इस गांव को सरकार से बहुत कम सहायता मिलती है। जंगलअखई पंचायत का बड़ा महुवासर गांव यहां का ऐसा ही एक अन्य गांव है जो रोहिणी नदी व तटबंध के बीच फंसा हुआ है। यहां के लगभग 150 परिवारों की समस्याएं कुछ वर्ष पहले और बढ़ गई जब तटबंध के दूसरे पार की उनकी सुरक्षित भूमि को थोड़ा–बहुत मुआवजा देकर जबरदस्ती अधिग्रहीत कर लिया गया।

यहां के लोगों पिछड़ी जातियों के छोटे किसान व भूमिहीनों ने बताया कि उन्होंने भूमि अधिग्रहण का बहुत विरोध किया पर उनकी बात नहीं सुनी गई। एक किसान ने कहा कि हमारी जो थोड़ी सी अच्छी जमीन सुरक्षित बची थी उसका अधिग्रहण कर लेना तो ऐसा था जैसे किसी व्यक्ति का सिर ही काट दिया जाए। यदि सरकार ने पहले ही निर्णय लिया होता कि जो गांव पहले से नदी व तटबंध के बीच फंसे पड़े हैं उनके प्रति विशेष रक्षा व सहायता की नीति अपनाई जाती तो यह अधिग्रहण रुक सकता था।

अतः यह जरूरी है कि भविष्य में ऐसे अन्याय को रोकने के लिए ऐसा निर्णय लिया जाए कि जो गांव तटबंध व नदी में फंसने के कारण बहुत सी कठिनाइयां पहले से झेल रहे हैं उनके प्रति विशेष सहायता व रक्षा का व्यवहार किया जाए। तटबंध बनाते समय उम्मीद की जाती है कि जो लोग तटबंध व नदी के बीच फंसेंगे उससे कहीं अधिक संख्या में लोगों को तटबंधों से सुरक्षा मिलेगी।

किंतु जब तटबंध टूट जाते हैं तो इससे सुरक्षित किए गए गांवों में जो क्षति होती है वह सामान्य बाढ़ से कहीं अधिक होती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2010 की बाढ़ में तटबंध टूटने से गोंडा जिले की रदौली पंचायत में जो विनाशलीला हुई वह सामान्य बाढ़ से कहीं अधिक भयानक थी। यहां के लोगों को कुछ वर्षों से सुरक्षित स्थान में रहने की आदत हो गई थी। इसलिए इस प्रलयकारी बाढ़ का सामना करने की उनकी तैयारी वैसे भी कम थी।

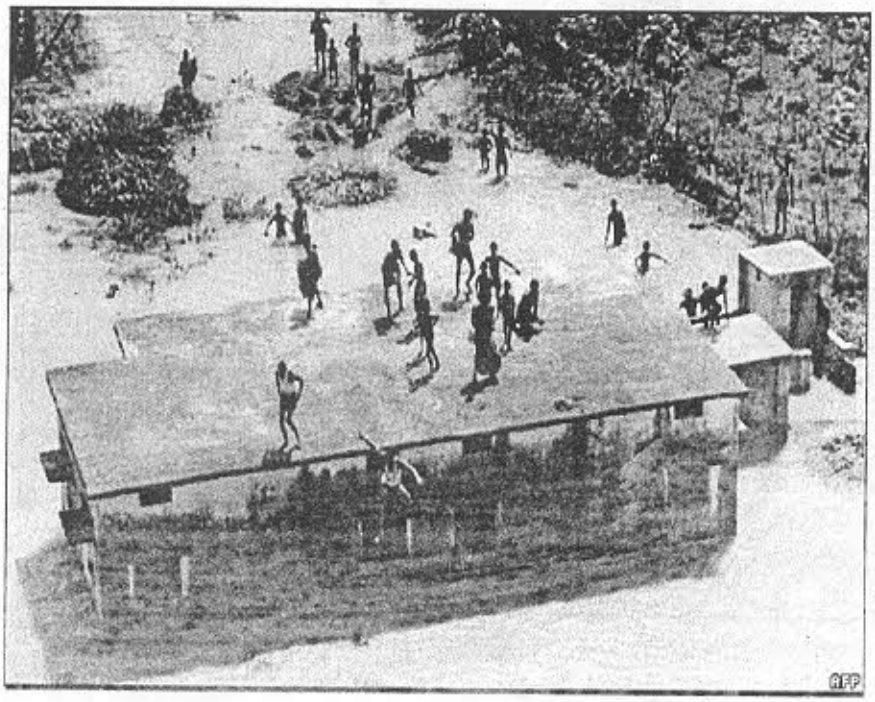

इस तरह की बाढ़ से अधिक विनाश होने पर गांववासी प्रायः दीर्घकालीन आर्थिक संकटों में फंस जाते हैं विशेषकर तब जब सरकारी राहत बहुत कम मिलती है व साहूकार ऊंचे ब्याज पर कर्ज देते हैं। यहां 10 प्रतिशत प्रति माह का ब्याज चलता है।

नदी कटान से अधिक प्रभावित गांव तो इससे भी बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। वास्तव में ऐसे अनेक गांव तो लगभग ध्वस्त हो चुके हैं या उनका अस्तित्व ही खतरे में है। अनेक गांवों में रोजी–रोटी की बिगड़ती स्थिति बाढ़ के बदलते रूप से जुड़ी हुई है। अनेक गांववासियों ने हमें बताया कि पहले बाढ़ आती थी और शीघ्र ही चली जाती थी पर अब बाढ़ और जल जमाव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। इस तरह एक ओर खरीफ की फसल नष्ट होती है तो दूसरी ओर रबी की फसल की समय पर बुवाई नहीं हो पाती।

नदी और तटबंध के बीच फंसे गांवों की बिगड़ती समस्याओं को प्रायः स्वीकार कर लिया जाता है, पर साथ ही यह कहा

बाढ़ से अधिक विनाश होने पर गांववासी प्रायः दीर्घकालीन आर्थिक संकटों में फंस जाते हैं विशेषकर तब जब सरकारी राहत बहुत कम मिलती है व साहूकार ऊंचे ब्याज पर कर्ज देते हैं। यहां 10 प्रतिशत प्रति माह का ब्याज चलता है। नदी कटान से अधिक प्रभावित गांव तो इससे भी बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं।

जाता है कि जो लोग तटबंधों द्वारा बाढ़ से सुरक्षित किए गए हैं, उनकी संख्या कहीं अधिक है। पर इस बारे में सवाल उठना जरूरी है कि यह सुरक्षा कितनी वास्तविक है।

प्राय तटबंध यदि सामान्य बाढ़ के पानी को रोकते हैं तो इसके साथ बहकर आने वाली उपजाऊ मिट्टी व गाद को भी रोक देते हैं। इस तरह सुरक्षित किए गए बाढ़ क्षेत्र निःशुल्क प्राप्त होने वाले प्राकृतिक खाद से भी वंचित हो जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि तटबंध नदी की बाढ़ का पानी रोकते हैं तो नदी में जाने वाले वर्षा के पानी को भी रोक देते हैं जिससे इन गांवों में दलदलीकरण व जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा तटबंध टूटने की स्थिति में सामान्य से अधिक विनाशक बाढ़ आती है।

हिमालय की नदियां प्रायः अपने विशाल जलग्रहण क्षेत्र से भारी मात्रा में मिट्टी व गाद लाती है और यदि कोई अवरोध न हो तो सामान्य बाढ़ के माध्यम से इसे बड़े क्षेत्रों में फैला देती हैं। तटबंध बनने के बाद यह मिट्टी व गाद बड़े क्षेत्रों में नहीं फैल पाता और इनके जमा होने से नदी का तल व जलस्तर ऊपर उठने लगता है। कुछ वर्षो में यह तटबंध की ऊंचाई तक आ जाता है जिस कारण तटबंध की ऊंचाई बढ़ानी पड़ती है। इस प्रक्रिया का एक दीर्घकालीन असर यह होता है कि बाढ़ से सुरक्षित की गई भूमि नदी से नीची रह जाती है। इस स्थिति में यदि तटबंध टूटता है तो ऊपर से नीचे की ओर तेजी से बहने वाली बाढ़ अधिक विनाशक होती है। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि तटबंधों से सुरक्षित लोगों की संख्या तटबंधों व नदी के बीच फंसे लोगों से कहीं अधिक है। यह भी कहना उचित नहीं है कि तटबंध बाढ़ नियंत्रण का असरदार उपाय हैं।

बाढ़ व जल जमाव के अधिक स्थायी होने का एक मुख्य कारण यह है कि सड़क, रेलवे लाइन, नहर, पुल, हाइवे आदि के बनने से और इनमें निकासी की उचित व्यवस्था न होने से जल की निकासी की व्यवस्था जगह–जगह पर बुरी तरह गड़बड़ा गई है।

बाढ़ व जल जमाव के अधिक स्थायी होने का एक मुख्य कारण यह है कि सड़क, रेलवे लाइन, नहर, पुल, हाइवे आदि के बनने से और इनमें निकासी की उचित व्यवस्था न होने से जल की निकासी की व्यवस्था जगह–जगह पर बुरी तरह गड़बड़ा गई है। हाल के वर्षों में तालाबों, झीलों जैसे अनेक जल–स्रोतों पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इस कारण इनका क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा है। इसके अलावा अनेक जल स्रोतों का तो अस्तित्व ही समाप्त हो गय है।

पहले वर्षा का जो पानी जलस्रोतों में समा जाता था व सूखे महीनों में मनुष्यों व जीव जंतुओं की आवश्यकता को पूरा करने के काम आता था वही जल अब जलस्त्रोतों के न रहने या उनके सूख जाने के कारण बाढ़ की स्थिति को अधिक उग्र बना रहा है। कई अपराधी व माफिया तत्व भी ऐसे अतिक्रमणों के लिए जिम्मेदार हैं। ❑

दृष्टिकोण

मुंबई की बाढ़ को रोकने का सिंगापुरी तरीका

मुंबई नगरी देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। फिल्म निर्माण हो अथवा व्यापार, सभी दृष्टि से मुंबई एक अत्यंत महत्वपूर्ण महानगर है। ऐसे में मुंबई का हर वर्ष बाढ़ में डूबना, विशेष चिंता का विषय है। आज जो मुंबई की स्थिति है, लगभग वैसी ही स्थिति 1950 के दशक में सिंगापुर की थी। आज सिंगापुर में बाढ़ इतिहास की बात बन चुकी है। बल्कि बारिश से आनेवाले जल का प्रबंधन करते हुये, आज सिंगापुर अपनी अधिकाधिक जल की आवश्यकताओं की आपूर्ति अपने इस जल प्रबंधन के माध्यम से करता है।

■ डॉ. अश्विनी महाजन

जहां मानसून आने से गर्मी से निजात पाने का सपना देश भर में सुखद अनुभूतियां लाता है तो दूसरी ओर कई वर्षों से बाढ़ झेल रही मुंबई एकदम सिहर जाती है। हजारों करोड़ रूपये का नुकसान, मानव दिनों की बर्बादी और बीमारियों के प्रकोप के चलते मुंबई के लिये बारिश एक अभिशाप बन चुकी है।

पिछले कुछ दिनों में धारवी, अंधेरी, हिन्दमाता, विलयपार्ले, कुर्ला, दादर, सांताक्रूज, विखरोली, चैम्बूर, सायन और परेल सहित मुंबई के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं।

लेकिन यदि हम मुंबई की बाढ़ का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तो पता चलता है कि मुंबई में बढ़ती जनसंख्या के दबाव के फलस्वरूप, नये निर्माणों ने मुंबई के छोटे बड़े नदी नालों को बंद कर दिया है और उसके कारण वर्षा के पानी की निकासी के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। थोड़ी सी बारिश भी मुंबई में बाढ़ का कारण बन सकती है और यदि बारिष कहीं ज्यादा हो जाये तो भयंकर बरबादी निष्चित है।

हम मुंबई की बाढ़ का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तो पता चलता है कि मुंबई में बढ़ती जनसंख्या के दबाव के फलस्वरूप, नये निर्माणों ने मुंबई के छोटे बड़े नदी नालों को बंद कर दिया है और उसके कारण वर्षा के पानी की निकासी के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। थोड़ी सी बारिश भी मुंबई में बाढ़ का कारण बन सकती है और यदि बारिश कहीं ज्यादा हो जाये तो भयंकर बरबादी निश्चित है।

सिंगापुर में बाढ़ बन चुकी है इतिहास

मुंबई नगरी देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। फिल्म निर्माण हो अथवा व्यापार, सभी दृष्टि से मुंबई एक अत्यंत महत्वपूर्ण महानगर है। ऐसे में मुंबई का हर वर्ष बाढ़ में डूबना, विशेष चिंता का विषय है। आज जो मुंबई की स्थिति है, लगभग वैसी ही स्थिति 1950 के दशक में सिंगापुर की थी। आज सिंगापुर में बाढ़ इतिहास की बात बन चुकी है। बल्कि बारिश से आनेवाले जल का प्रबंधन करते हुये, आज सिंगापुर अपनी अधिकाधिक जल की आवश्यकताओं की आपूर्ति अपने इस जल प्रबंधन के माध्यम से करता है।

हुआ यूं कि 1954 में मलेशिया ने सिंगापुर को स्वयं से अलग कर दिया। तब सिंगापुर एक साधन विहीन देश था। यहां तक कि उसके पास स्वयं के लिये आवश्यक जल की आपूर्ति भी नहीं थी। मलेशिया से जल आपूर्ति के संबंध में मलेशिया से 1961 और 1962 में किए गए समझौतों के अनुसार एक सीमित के लिये 1 सेंट प्रति 1000 गैलन की कीमत पर जल आपूर्ति कराने का प्रावधान रखा गया।

ऐसे में सिंगापुर ने अपने राष्ट्रीय

हितों और स्वाभिमान को बनाये रखने के लिये यह तय किया कि उस अवधि के समाप्त होने तक सिंगापुर का जल प्रबंधन इस प्रकार से करेंगे कि वे न केवल जल आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे, बल्कि बाढ़ की समस्या का समाधान भी साथ ही साथ कर लिया जायेगा।

सिंगापुरी जल प्रबंधन

700 वर्ग किलोमीटर के इस शहरनुमा देश के पास अपनी कोई नदी भी नहीं है। पिछले दो दशकों में सिंगापुर के जल प्रबंधन में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। कुछ समय पूर्व सिंगापुर का 15वां जलाशय बनाया गया है। इस जलाश्य की खूबी यह है कि समुद्र पर बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया है। पहले से निर्मित दो जलाशयों के साथ जोड़ कर इस जलाशय को बनाया गया है। पूरे सिंगापुर शहर में जल निकासी के लिये भूमिगत नालियों का निर्माण किया गया है। बारिश का पानी इन नालियों के माध्यम से जलाशय में पहुंचता है। यह जलाशय 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र यानि सिंगापुर के लगभग छठे हिस्से से जल इकट्ठा करता है। जब इस जलाशय में पानी अधिक भर जाता है, समुद्र के साथ बने होने के कारण उसे समुद्र में डाल दिया जाता है। समुद्री लहरें नीची होने की दशा में तो यह पानी स्वयं समुद्र में चला जाता है और यदि समुद्री लहरें ऊंची हों तो उस दशा में बांध पर बने पानी के पंप स्वचालित ढंग से चालू हो जाते हैं और उस दशा में भी पानी समुद्र में चला जाता है।

इस जल प्रबंधन की नायाब विधि वाले इस जलाशय का नाम 'मेरिना बराज' है और वह आजकल सिंगापुर में अन्य दर्शनीय स्थलों के साथ–साथ पर्यटकों के लिए आकर्षण बन रहा है। 'मेरिना बराज' पर बने संग्रहालय में 1954 के वर्ष में सिंगापुर की भयंकर बाढ़ के चित्र भी है और वर्तमान जल प्रबंधन की नायाब विधि के चित्रों के साथ उसकी कार्यशैली का क्रियाशील मॉडल भी रखा गया है।

मुंबई भी ले सकती है सबक

मुंबई और सिंगापुर की लगभग एक जैसी स्थिति है। दोनों समुद्र के किनारे बसे, बड़ी जनसंख्या वाले शहर हैं। सिंगापुर की भांति हालांकि मुंबई में पानी की गुजारे लायक व्यवस्था है, लेकिन बारिश के दिनों के अतिरिक्त अक्सर मुंबई वासियों पर पानी की कमी की तलवार लटकी रहती है। दूसरे हल्की सी बारिश होते ही, मुंबई में जल भरन की समस्या शुरू हो जाती है। जून 2011 के दूसरे सप्ताह में थोड़ी बहुत बारिश होते ही जल भरन की प्रवृत्ति बाढ़ के किसी बड़े प्रकोप का संकेत भी कहीं न कहीं दे ही रही है। ऐसे में बड़े नुकसान के बार–बार सहने से अच्छा तो यही होगा कि मुंबई (महाराष्ट्र) सरकार सिंगापुर की तर्ज पर केन्द्र सरकार के साथ मिलकर मुंबई जल प्रबंधन की योजना तैयार करे।

ऐसे में बड़े नुकसान के बार–बार सहने से अच्छा तो यही होगा कि मुंबई (महाराष्ट्र) सरकार सिंगापुर की तर्ज पर केन्द्र सरकार के साथ मिलकर मुंबई जल प्रबंधन की योजना तैयार करे।

हो सकता है प्रारंभ में यह योजना एक महत्वकांक्षी योजना लगे, लेकिन अंतोगत्वा मुंबई में वर्षा के जल का संचयन मुंबई की जल समस्या को तो निदान देगा ही, साथ ही साथ बाढ़ की त्रासदी से भी मुक्ति मिलेगी।

मुम्बई में भूमि की कमी के चलते, बढ़ती जनसंख्या और उससे भी अधिक भू–माफिया के बढ़ते दबाव के कारण मुम्बई में नदी नालों को बंद करने के कारण जल का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हुआ और हल्की सी बारिश भी जल भरण का कारण बनना शुरू हो गई। बहुत वर्ष पहले मुम्बई में एक मीठी नदी बहा करती थी। उस मीठी नदी के किनारे कोई निर्माण नहीं था, लेकिन आज उस मीठी नदी का आस्तित्व ही लगभग समाप्त हो चुके है। इसी प्रकार मुम्बई के एक प्रमुख नाले को बंद करते हुए एक बड़ी सड़क बना दी गई है। इसके अलावा भी पूर्व के अनगिनत नाले अब लगभग समाप्त हो गये हैं। यानि कहा जा सकता है कि आज मुम्बई की जल निकासी के सभी पुराने रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे में वर्षा का पानी बड़ी बाढ़ का कारण ही नहीं बनता बल्कि वह तबाही करता हुआ समुद्र में भी चला जाता है।

आज मुम्बई में पानी की भी भारी समस्या है। मुम्बई वासियों को आज प्रति व्यक्ति मात्र 90 लीटर पानी ही उपलब्ध है, जबकि उसकी आवश्यकता 135 लीटर प्रति व्यक्ति है। स्लम बस्तियों में तो यह मात्र 25 लीटर प्रति व्यक्ति ही उपलब्ध है। वर्तमान में मुम्बई की आवश्यकताओं की पूर्ति मुम्बई से बाहर बहने वाली नदियों से ही होती है। मुम्बई की जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य की योजनाएं भी वैतरना नदी पर बांध बनाकर पूरा करने की है। ऐसे में यदि मुम्बई के वर्षा के जल का सही प्रबंधन किया जा सके तो मुम्बई द्वीप शहर अपनी बाढ़ की समस्या के समाधान के साथ–साथ अपनी जल आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा आस–पास की बस्तियों के लिए भी पानी उपलब्ध करा सकता है। ❑

वैश्विक कर्ज संकट से मुश्किलें

भारत की मजबूती के कई कारण हैं। यहां आर्थिक उदारीकरण के दो दशक बीत चुके हैं। जुलाई 1991 से अगस्त 2011 के बीच आर्थिक सुधारों से देश वैश्वीकरण की ओर आगे बढ़ा है। फिर भी अब अमेरिकी, जापानी और यूरोपीय आर्थिक संकट के बीच भारत को सतर्क होने की जरूरत है। भारत ने 41 अरब डॉलर के अमेरिकी बांड ले रखे हैं तथा देश के विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा भाग डॉलर में है। अमेरिका और यूरोप के बाजार की भारत के निर्यात में 35 प्रतिशत हिस्सेदारी है

■ डॉ. जयंती भंडारी

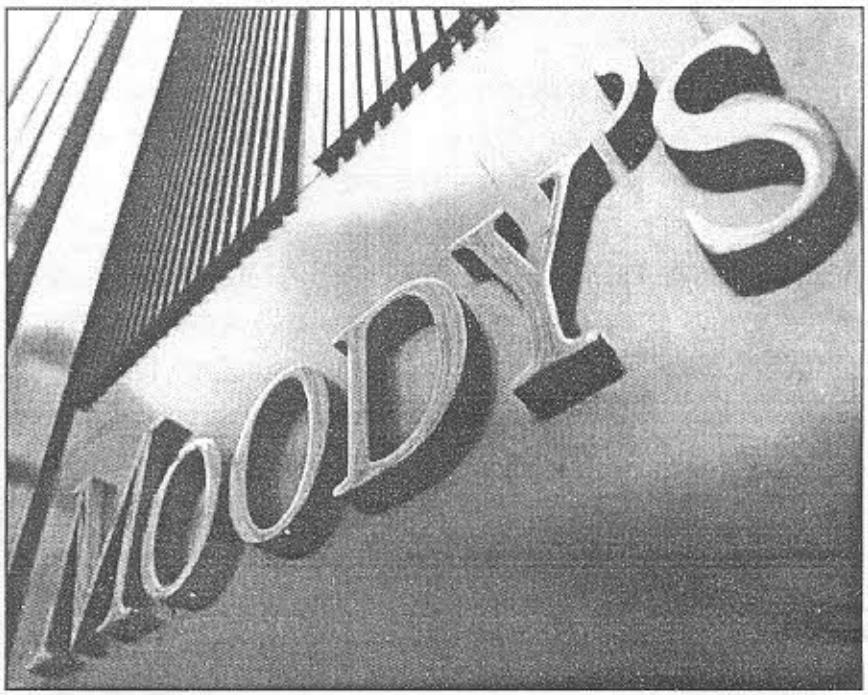

निसंदेह जैसे–जैसे वैश्विक कर्ज संकट बढ़ रहा है, वैसे–वैसे दुनिया की आर्थिक मुश्किलें बढ़ रही हैं। कोई एक माह पहले जब 5 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंर्डड एंड पुअर्स ने पहली बार अमेरिका की सॉवरिंग रेटिंग में कमी करके इसे ट्रिपल ए से घटाकर डबल ए प्लस कर दिया है, तो रेटिंग में यह गिरावट यह संकेत दे रही है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है और एक राजकोषीय संकट ने उसे लकवाग्रस्त बना दिया है।

अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग घटने से दुनिया के बाजारों को तगड़े झटके लगे हैं और 2008 की मंदी के बाद इस समय शेयर बाजार जबर्दस्त गिरावट की स्थिति में दिख रहे हैं। अभी अमेरिका की रेटिंग कम होने के आर्थिक असर से दुनिया उभर भी नहीं पाई थी कि एक और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 24 अगस्त को जापान की रेटिंग को ट्रिपल ए से घटाकर डबल ए प्लस कर दिया है। एशिया की महाशक्ति जापान की रेटिंग कम करके दुनिया की मंद इकोनॉमी को और अस्थिरता– अनिश्चितता के चक्रव्यूह में डाल दिया गया है।

अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग घटने से दुनिया के बाजारों को तगड़े झटके लगे हैं और 2008 की मंदी के बाद इस समय शेयर बाजार जबर्दस्त गिरावट की स्थिति में दिख रहे हैं। अभी अमेरिका की रेटिंग कम होने के आर्थिक असर से दुनिया उभर भी नहीं पाई थी कि एक और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 24 अगस्त को जापान की रेटिंग को ट्रिपल ए से घटाकर डबल ए प्लस कर दिया है।

इसी तरह यूरोप में भी डगमगाती अर्थव्यवस्थाएं दिख रही हैं। नई आशंकाएं जोर पकड़ रही हैं कि अमेरिका और यूरोप दोनों में फिर से मंदी दस्तक देती हुई दिखाई दे रही है। जहां ढेर सारी आर्थिक–सामाजिक चुनौतियों से अमेरिका, यूरोप और जापान के लिए अपनी–अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभालना मुश्किल हो रहा है, वहीं अमेरिका का असर पूरी दुनिया पर सबसे अधिक पड़ते हुए दिखाई दे रहा है।

इस बीच अमेरिका में आए तूफान आइरीन ने उसकी मुश्किलों को और बढ़ाया है। दरअसल, अमेरिका पर 11 सितम्बर, 2001 के आतंकी हमले के बाद जो बुरे वित्तीय प्रभाव पड़े, उसे दो युद्धों– इराक तथा अफगानिस्तान में अमेरिका की सक्रियता ने और गहरा दिया। जल्द ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था राजकोषीय घाटे की स्थिति में पहुंच गई। इसके बाद व्यापार घाटे में भारी वृद्धि ने इसमें और इजाफा किया।

तत्पश्चात लीमन ब्रदर्स के दिवालिया होने की घटना के बाद अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई और उस पर नियंत्रण के लिए अर्थव्यवस्था को जबर्दस्त वित्तीय मदद की आवश्यकता पड़ी। अमेरिका में इस आर्थिक मंदी से बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई और उससे वहां पर गरीब लोगों की संख्या बढ़ी। मंदी के बाद जहां अमेरिका में गरीब लोग बढ़े, वहीं बेरोजगारी भी बढ़ी। अब तक अमेरिका में रोजगार की स्थिति सुधरी नहीं है। अगस्त 2011 की शुरुआत में आए आंकड़ों में अमेरिका में बेरोजगारी की दर 9.2 फीसद दर्ज की गई है।

अमेरिका में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिन्हें साल में छह महीने बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। स्थिति यह है कि राष्ट्रपति ओबामा के सामने बेरोजगारी से निपटने की सबसे बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा है उसके चलते ओबामा की टैक्स कम करने और सरकारी खर्च को घटाने की नीतियां लागू करना व्यावहारिक नहीं दिख रहा है।

चूंकि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं इसलिए पूरी दुनिया के साथ एशिया पर भी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के कर्ज संकट तथा क्रेडिट रेटिंग घटने का असर पड़ रहा है।

खासतौर से चीन, भारत, दक्षिण कोरिया जैसी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रही हैं। 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के समय इन देशों ने विश्व अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा सहारा दिया था। जब अमेरिका में मंदी से हाहाकार मचा हुआ था तो उस समय भारत और चीन जैसे देशों में आर्थिक वृद्धि दर काफी अच्छी थी।

खासतौर से भारत में कृषि अर्थव्यवस्था और बचत दर के कारण लीमन जैसी किसी घटना के बाद आर्थिक पैकेज देने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। भारत की मजबूती के कई कारण हैं। यहां आर्थिक उदारीकरण के दो दशक बीत चुके हैं। जुलाई 1991 से अगस्त 2011 के बीच आर्थिक सुधारों से देश वैश्वीकरण की ओर आगे बढ़ा है। फिर भी अब अमेरिकी, जापानी और यूरोपीय आर्थिक संकट के बीच भारत को सतर्क होने की जरूरत है। भारत ने 41 अरब डॉलर के अमेरिकी बांड ले रखे हैं तथा देश के विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा भाग डॉलर में है। अमेरिका और यूरोप के बाजार की भारत के निर्यात में 35 प्रतिशत हिस्सेदारी है और इन देशों में भारतीय निर्यात के जो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उनमें जेम एंड ज्वैलरी, लेदर, टेक्सटाइल, आईटी, फॉर्मा और कुछ अन्य सेवा क्षेत्र शामिल हैं। चूंकि अमेरिका और यूरोप भारतीय निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है इसलिए अब वहां खर्चे में कटौती की जो प्रक्रिया चल रही है, उससे भारतीय निर्यातकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।

चूंकि हमारा विदेश व्यापार असंतुलन तेजी से बढ़ता जा रहा है, अतएवं हमें एक ओर मंदी की चुनौतियों के बीच भी निर्यात बढ़ाने होंगे, वहीं दूसरी ओर आयात को नियंत्रित करने की रणनीति बनानी होगी। जहां विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा एक फीसद है, वहीं चीन का हिस्सा दस फीसद है। इस समय निर्यात में जबर्दस्त इजाफे के बाद 1.20 लाख करोड़ डॉलर का निर्यात रिकॉर्ड बनाते हुए चीन जर्मनी से आगे निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा

भारतीय निर्यात को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए निर्यातकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अभी अधिकतर निर्यातकों को प्रत्येक निर्यात आदेश के परिप्रेक्ष्य में एक साल की अवधि के लिए करीब 13–14 फीसद ब्याज दर पर ऋण लेने को बाध्य होना पड़ता है। वस्तुतः यह दर चीन सहित दुनिया के अन्य देशों की तुलना में लगभग आठ से नौ फीसद ज्यादा है।

निर्यातक बन गया है।

लेकिन जिन देशों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं, उनमें से अधिकतर देशों के साथ चीन के भी एफटीए हैं। आसियान देशों के साथ भारत के एफटीए के लागू होने से आसियान बाजार में पहले से वर्चस्व जमाए चीन के साथ भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है।

स्थिति यह बनी है कि भारत को एफटीए वाले देशों के बाजारों में ताकतवर खिलाड़ी चीन से व्यापार में सीधे लोहा लेना पड़ रहा है। चूंकि चीन भारत से औसतन 30 प्रतिशत कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, सो उससे व्यापार में मुकाबले के लिए भारत को कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करने वाले देश के रूप में बाजार पहचान बनानी होगी।

भारतीय निर्यात को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए निर्यातकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अभी अधिकतर निर्यातकों को प्रत्येक निर्यात आदेश के परिप्रेक्ष्य में एक साल की अवधि के लिए करीब 13–14 फीसद ब्याज दर पर ऋण लेने को बाध्य होना पड़ता है। वस्तुतः यह दर चीन सहित दुनिया के अन्य देशों की तुलना में लगभग आठ से नौ फीसद ज्यादा है। हमें देश में बढ़ते हुए आयातों के खतरों को भी समझना होगा। छलांगें लगाकर बढ़ते हुए आयातों की गति रोकनी होगी। साथ ही आयातित सामान की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। हमें ध्यान देना होगा कि कई आयातित माल पर एंटी डम्पिंग ड्यूटी न बढ़ने से घरेलू उत्पादों का बाजार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में जरूरी है कि चीन जैसे कुछ देशों से आयातित कुछ उत्पादों पर एंटी डम्पिंग ड्यूटी को बढ़ाया जाए, ताकि सस्ते विदेशी उत्पादों और देशी उत्पादों के बीच में प्रतिस्पर्धा के स्तर को बराबर रखा जा सके। यकीनन हमें वैश्विक आर्थिक संकट की आसन्न चुनौतियों के बीच आर्थिक मोर्चे पर कुछ जोरदार कदम उठाने होंगे। हमें देश की अर्थव्यवस्था को निर्यात पर आश्रित नहीं बनाना है। क्योंकि वैश्विक मंदी के दौर में निर्यात पर टिकी अर्थव्यवस्थाओं का हश्र हम देख चुके हैं। ❑

सदस्यता संबंधी सूचना

मान्यवर,,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि "स्वदेशी पत्रिका" के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है।

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	100/–	1000/–
अंग्रेजी	100/–	1000/–

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

पता : **स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22**

पुराने उपायों से संभव नहीं समाधान

महंगाई से रिजर्व बैंक पुराने जमाने में कुछ ऐसे निपटता था कि ब्याज की दरें महंगी कर दी जायें। इसके कारण तमाम चीजें महंगी हो जाया करती थीं और जब तमाम चीजें महंगी हो जाती थीं, तो उन आइटमों की मांग कम हो जाती थी। मांग कम होने से वस्तुओं की कीमतें स्वतः कम होने लगती थीं, और महंगाई काबू में आ जाती थी पर अब ऐसा नहीं है।

■ आलोक पुराणिक

पुरानी समस्याएं होती थीं, पुराने उपायों से निपट जाया करती थीं। महंगाई भी उनमें से एक है। महंगाई से रिजर्व बैंक पुराने जमाने में कुछ ऐसे निपटता था कि ब्याज की दरें महंगी कर दी जायें। इसके कारण तमाम चीजें महंगी हो जाया करती थीं और जब तमाम चीजें महंगी हो जाती थीं, तो उन आइटमों की मांग कम हो जाती थी। मांग कम होने से वस्तुओं की कीमतें स्वतः कम होने लगती थीं, और महंगाई काबू में आ जाती थी पर अब ऐसा नहीं है।

अब हो यह रहा है कि भाव तो बढ़ रहे हैं सब्जियों आदि खाद्य वस्तुओं के जिनकी मांग में भी बढ़ोतरी हो रही और रिजर्व बैंक ब्याज दर महंगी कर रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि ब्याज दरें महंगी होने से खाद्य वस्तुओं से इतर आइटमों की मांग कम हो रही है। यानी नतीजा यह है कि टमाटर के भाव कम करने के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं, उनके परिणाम स्वरूप कारों का बिक्री कम हो रही है। 20 अगस्त 2011 को खत्म हुए महीने में खाद्यान्न महंगाई थोक मूल्यों के आधार पर बढकर 10.05 फीसद हो गयी। यानी एक वर्ष में खाने–पीने की चीजों के थोक मूल्य में करीब दस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। रिटेल क्षेत्र में यह बढ़ोत्तरी और भी ज्यादा है।

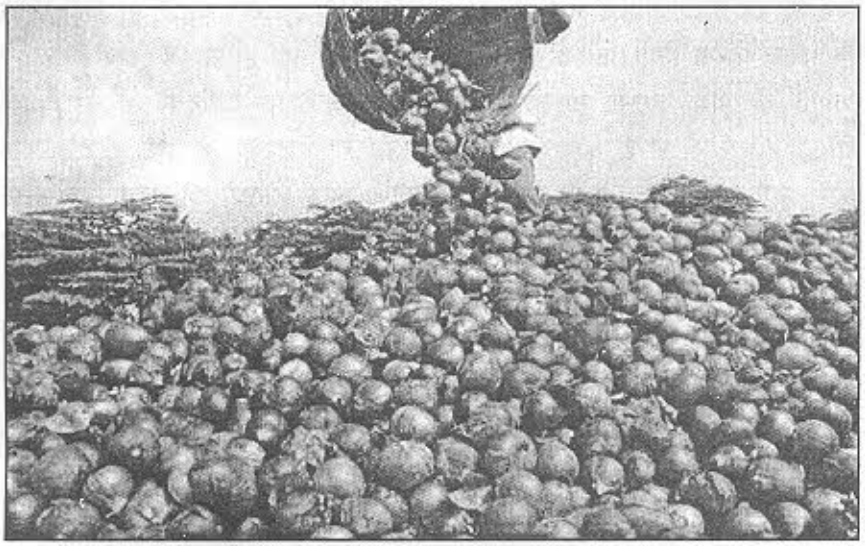

प्याज एक साल में करीब 57 फीसद महंगा हो गया है। महंगाई के ये परिणाम देखकर रिजर्व बैंक घबराता है और उसके पास एकमात्र उपाय रह जाता है कि ब्याज की दरों को बढ़ा दिया जाए। इस रूप में मार्च, 2010 से रिजर्व बैंक अब तक ग्यारह बार ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी कर चुका है। अभी 16 सितम्बर को फिर मीटिंग होने वाली है। उम्मीद है कि इस मीटिंग में भी ब्याज की दरें बढ़ा दी जाएंगी।

प्याज एक साल में करीब 57 फीसद महंगा हो गया है। महंगाई के ये परिणाम देखकर रिजर्व बैंक घबराता है और उसके पास एकमात्र उपाय रह जाता है कि ब्याज की दरों को बढ़ा दिया जाए। इस रूप में मार्च, 2010 से रिजर्व बैंक अब तक ग्यारह बार ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी कर चुका है। अभी 16 सितम्बर को फिर मीटिंग होने वाली है। उम्मीद है कि इस मीटिंग में भी ब्याज की दरें बढ़ा दी जाएंगी।

ब्याज की दर बढ़ने का हाल यह हुआ है कि वह उद्योग जगत बुरी तरह परेशान हो गया है जिसकी बिक्री ब्याज दरों पर ही निर्भर करती है। जैसे कार उद्योग की हालत इस समय बहुत खराब है। कार उद्योग की करीब पचहत्तर प्रतिशत खरीद उधारी के बल पर होती है। जाहिर है, उधारी पर ब्याज बढ़ता है, तो ईएमआई बढ़ जाती है और इसका परिणाम यह हो रहा है कि कारों की बिक्री लगातार नीचे गिरती जा रही है।

कुछ महीनों पहले कुछ कारों को खरीदने के लिए वेटिंग पीरियड हुआ

करता था पर आज हालात यह हैं कि कस्टमर तलाशना मुश्किल हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप कार कंपनियां अपना उत्पादन लगातार कम करने में लगी हुई हैं।

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति ने अगस्त 2011 में 77,086 कारें बेचीं जबकि अगस्त 2010 में इस कंपनी ने 92,674 कारें बेची थीं। यानी एक साल के अंदर उसकी बिक्री में 16.82 फीसद की गिरावट आ गयी है।

टाटा मोटर्स नैनो के बावजूद मंदी से नहीं बच पायी है। टाटा मोटर्स ने अगस्त 2011 में 16,829 कारें बेचीं, जबकि अगस्त 2010 में इसने 25,212 कारें बेचीं थी। यानी एक साल में टाटा मोटर्स की कारों की सेल में 33.25 प्रतिशत की गिरावट आ गयी है।

बहरहाल महंगाई को कम करने के उपाय के रूप में ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं जिसके कारण कार उद्योग सकते में है। कस्टमर बहुत मुश्किल से हाथ आ रहे हैं। ऐसे माहौल में यह आशंकाएं और गर्म हो गई हैं कि आगामी 16 सितम्बर को रिजर्व बैंक फिर से ब्याज दर बढ़ाने जा रहा है।

दरअसल पुराने और नये माहौल में एक बहुत बड़ा फर्क यह आ गया है कि खाने–पीने की चीजों की मांग लगातार बढ़ती रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज वह वर्ग भी इस मांग में शामिल हो चुका है जिसकी पहले इस तक पहुंच नहीं होती थी। आज के समय में क्रय शक्ति अर्थव्यवस्था के निचले स्तर तक पहुंच चुकी है। जिसकी वजह से फल और सब्जियों की मांग वहां से भी आ रही है।

ऐसा होने का कारण यह है कि तमाम सरकारी योजनाओं ने उस वर्ग तक क्रयशक्ति को पहुंचाया है। पर उस क्रय शक्ति के परिणाम ये हैं कि मांग कम होने का नाम नहीं ले रही है। कारण टमाटर, प्याज का हाल कार उद्योग की तरह नहीं होता कि जब चाहे उत्पादन कम कर लो और जब चाहे बढ़ा लो।

अभी मांग में कमी के चलते तमाम कार कंपनियों ने अपना उत्पादन कम किया है। पर टमाटर, प्याज का उत्पादन बढ़ाने या कम करने में महीनों लग जाते हैं। यानी कुल मिलाकर हो यह रहा है कि बीमारी कुछ और है और इलाज कुछ और तलाशा जा रहा है। नई बीमारी का इलाज पुराने ही तरीके से हो रहा है, क्योंकि वह इलाज किताबों में दर्ज है।

क्योंकि पहले इस इलाज से सकारात्मक परिणाम आ जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। सच्चाई यह है कि अब यदि टमाटर और प्याज के भाव बढ़ रहे है तो टमाटर और प्याज का ही इलाज करना होगा। इनकी मांग और आपूर्ति के बीच जरूरी संतुलन लाना होगा। और पहले से ही आकलन करना होगा। अभी तो होता यह है कि जब रिटेल बाजार में कीमतें आसमान छूने लग जाती हैं, तब जाकर सरकार हरकत में आती है। हाल में अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान तो लगा कि सरकार ने इस दिशा में कुछ भी काम करना बंद कर दिया है। आंदोलन के समाप्त होने के बाद हल्ला हुआ कि प्याज के भाव तो फिर से आसमान छूने लगे गये हैं। पर चूंकि अभी कहीं चुनाव नहीं हैं इसलिए इस मुद्दे ने बहुत जोर नहीं पकड़ा है।

सबसे महत्वपूर्ण मसला यह है कि प्याज, टमाटर, और आलू जैसे रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं की सप्लाई कैसे बढ़ायी जाये। देश के किसानों का हाल यह है कि वह खेती किसानी छोड़कर दूसरे धंधों की तरफ जाना चाहते हैं। दूसरी ओर बड़ी कंपनियां फार्मिंग के क्षेत्र में जाना चाहती हैं पर उन्हे इजाजत नहीं है। आज के हालात देखते हुए नीतिगत स्तर पर कुछ ऐसा हो कि व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर फार्मिंग की अनुमित बड़ी कंपनियों को दे दी जाये और तमाम खाद्य वस्तुओं की पैदावार बढ़ायी जाये।

बड़ी कंपनियां संसाधन, लागत के स्तर पर खेती का प्रबंधन बेहतर तरीके से कर सकती हैं। मतलब यह भी हो सकता है कि तमाम खेतों का मालिकाना हक बेशक छोटे किसानों के पास ही रहे, पर बड़ी कंपनियों को उससे उपज लेने का अधिकार मिल जाए। जब नये खरीदार बाजार में आ गये हैं, तो नये बिकवाल भी तो बाजार में आने चाहिए। और यही नहीं हो रहा है। दुखद और विडम्बनापूर्ण बात यह है कि इन सारे मसलों पर कहीं गंभीर विमर्श भी नहीं हो रहा है। अब अगर इन सारे मसलों पर गंभीर विमर्श नहीं किया गया, तो भ्रष्टाचार से बड़ा मसला प्याज जैसी खाद्य वस्तुओं की महंगाई का बनने वाला है। आज नीतिगत स्तर पर कुछ ऐसा हो कि व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर खेती की अनुमति बड़ी कंपनियों को दी जाये और तमाम खाद्य वस्तुओं की पैदावार बढ़ायी जाये। बड़ी कंपनियां संसाधन, लागत के स्तर पर खेती का प्रबंधन बेहतर तरीके से कर सकती हैं।

मतलब यह भी हो सकता है कि तमाम खेतों का मालिकाना हक बेशक छोटे किसानों के पास ही रहे, पर बड़ी कंपनियों को उससे उपज लेने का अधिकार मिल जाए। जब नये खरीदार बाजार में आ गये हैं, तो नये बिकवाल भी तो बाजार में आने चाहिए। ❑

मुद्दा

क्यों नहीं सफल है एयर इंडिया?

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं "जैसे जीभ पर रखी हुयी जहर की बूंद का स्वाद न लेना संभव नहीं है, उसी तरह सरकरी अधिकारियों द्वारा राजस्व के एक भाग को न हड़पना सम्भव नहीं है। जैसे पानी के अन्दर तैर रही मछली ने कितना पानी पिया पता लगाना संभव नहीं है, वैसे ही सरकारी अधिकारियों द्वारा कितने धन की चोरी की गयी पता लगाना संभव नहीं है।" यह कठिन परिस्थिति तब है जब मंत्री ईमानदार हों। यदि मंत्री भी भ्रष्ट हों तो समस्या की गंभीरता का अनुमान पाठक स्वयं लगा सकते हैं। यही एयर इंडिया की कहानी है।

पानी के अन्दर तैर रही मछली ने कितना पानी पीया पता लगाना संभव नहीं है, वैसे ही सरकारी अधिकारियों द्वारा कितने धन की चोरी की गयी पता लगाना संभव नहीं है।" यह कठिन परिस्थिति तब है जब मंत्री ईमानदार हों। यदि मंत्री भी भ्रष्ट हों तो समस्या की गंभीरता का अनुमान पाठक स्वयं लगा सकते हैं। यही एयर इंडिया की कहानी है।

सीएजी की ड्राफ्ट रपट में बताया गया है कि एयर इंडिया ने लाभकारी रूटों का त्याग किया है। 2005 में अमृतसर से बर्मिंघम के लाभप्रद रूट पर सेवाएं शुरू की गयी थीं। तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुये इस उड़ान को 2008 में बन्द कर दिया गया। इसके बाद जेट एयरवेज ने इस रूट पर सेवा शुरू कर दी। इसी तरह कोलकाता–ढाका एवं कोलकाता–बैंकाक रूटों पर सेवायें बन्द कर दी गयीं। इसके बाद जेट एयर वेज और किंग फिशर ने इन रूटों पर सेवायें शुरू कर दीं। दिल्ली–कोची, कोची–कुवैत तथा कोची–मसकट के रूटों को भी एयर इंडिया ने बन्द कर दिया है।

एयर इंडिया ने 2005 में 111 हवाई जहाज खरीदने का 44,000 करोड़ का अनुबन्ध किया––उस समय जब कम्पनी का मार्केट शेयर घट रहा था और कम्पनी घाटे में चल रही थी। वर्ष 2000 और 2005 के बीच एयर इंडिया ने ड्राई लीज पर 28 हवाई जहाज लिये जबकि इन्हें उड़ाने के लिये कम्पनी के पास पायलेट नहीं थे। एयर इंडिया में एक हवाई जहाज के पीछे दूसरी कम्पनी की तुलना में सर्वाधिक कमर्चारी हैं। अनावश्यक हवाई जहाज खरीदने तथा लीज पर लेने तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करने में मंत्रियों एवं अधिकारियों का निजि स्वार्थ दिखता है।

सार्वजनिक इकाईयों के शीर्ष अधिकारियों के लिये दो रास्ते खुले रहते हैं। एक रास्ता कम्पनी को लाभप्रद बनाने का है। इसमें कर्मचारियों से संघर्ष करना पड़ता है। विशेषकर ऐसी सेवा में जिसमें ग्राहक से विनम्र व्यवहार नितांत जरूरी है। तकनीकी समस्या को हल करने में भी श्रम होता है। इसका हवाला देकर लाभप्रद रूटों को बन्द करना ज्यादा आसान होता है। मंत्रियों एवं दूसरे उच्च अधिकारियों का भी सामना करना पड़ता है।

मंत्री महोदय चाहते हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र को एयर सर्विस से जोड़ दिया जाये। परन्तु कम्पनी के लिये यह घाटे का सौदा होता है। एमडी बात न माने तो उसे मंत्री का कोपभाजन बनना पड़ता है। अधिकारी के लिये ज्यादा आसान होता है कि मंत्री के कहे अनुसार चले चाहे कम्पनी घाटे में जाये। एयर इंडिया के उच्च अधिकारी ने कहा कि सरकारी अधिकारियों की मांगों से मैं इतना परेशान हूं कि लगता है कि मेरे 100 बॉस हैं। ऐसे में शीर्ष अधिकारियों के लिये आसान होता है कि मंत्रियों के साथ मिलकर वे भी कम्पनी का दोहन करें। यह परिस्थिति केवल एयर

इंडिया की ही नहीं है तमाम सार्वजनिक इकाइयों की है। महानगर टेलिफोन निगम एवं प्रसार भारती भी इसी समस्या से जूझते हुये घाटे में चल रहे हैं।

मंत्रियों एवं उच्चाधिकारियों के किये भी कम्पनी को घाटे पर चलाते रहना लाभप्रद रहता है। खरीद में कमीशन, चहेतों की नियुक्ति, मनचाहे रूटों पर आवागमन आदि की सुविधायें इन्हें मिल जाती हैं। ये सुविधायें मिलती रहें इसलिये एयर इंडिया का निजिकरण करने के स्थान पर उसे और वित्तीय सहायता देने की नीति ये अधिकारी लागू करते हैं। हाल में सरकार ने 800 करोड़ रुपये की राशि एयर इंडिया को इक्विटी के रूप में दी है। इस रकम का उपयोग एयर इंडिया को घाटे में अधिक समय तक चलाने के लिये किया जायेगा ताकि मंत्रियों और अधिकारियों को सुविधायें चिरकाल तक मिलती रहें। कम्पनी को लाभप्रद बनाने के लिये कर्मचारियों का मनोबल सुधारना, अकुशल एवं अधिक कर्मचारियों की छुट्टी करना, घाटे के रूटों को समाप्त कर लाभप्रद रूटों पर सेवायें बढ़ाना, अधिक संख्या में उपलब्ध हवाई जहाजों को लौटाना आदि करना होगा। इन कदमों को उठाने में एमडी को मशक्कत करनी होगी। हड़ताल का सामना करना होगा। सचिव महोदय की नाराजी झेलनी होगी। इन झंझटों में पड़ने के स्थान पर एमडी के लिये सुलभ है कि वह और पूंजी की मांग करे और मंत्री के लिये भी यही आसान है।

वास्तविक सुधार के उपरोक्त कदमों को उठाने के स्थान पर एयर इंडिया द्वारा किराया घटाकर ग्राहक को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। खर्च कम करने के लिये कर्मचारियों के इन्सेंटिव काटे जा रहे हैं। यह फार्मूला कत्तई सफल नहीं होगा। किराया कम करने से घाटा तो बढ़ेगा ही। खर्च में कटौती के बाद ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी यह संदिग्ध है। कर्मचारियों के इन्सेंटिव घटाने से उनका मनोबल घटेगा और वे ग्राहक के साथ रूखा व्यवहार करेंगे।

आस्ट्रेलिया स्थित रिसर्च कम्पनी सेन्टर फार एशिया पैसिफिक एविएशन के प्रमुख पीटर हार्बिसन के अनुसार "दूसरे विकासशील देशों की सरकारी एयर लाइनों की भी समस्यायें हैं, परन्तु एयर इंडिया के समान कठिन परिस्थिति किसी दूसरे की नहीं है।" हर्बिसन बताते हैं कि इंडोनेशिया की गरूड़ एयरलाइन्स इसी तरह की समस्याओं से ग्रस्त थी। गरूड़ के हवाई जहाजों को असुरक्षित माना जाता था और यूरोपीय हवाई अड्डों पर उन्हें उतरने की इजाजत नहीं थी। तब उद्यमी एमिरस्याह सत्तार को कम्पनी की कमान सौंप दी गई। शीघ्र ही कम्पनी लाभ कमाने लगी।

हमें समझना चाहिये कि व्यापार एवं राजनीति के लिये बिल्कुल अलग–अलग व्यक्तित्व की जरूरत होती है। मंत्री और सरकारी अधिकारी मूलतः क्षत्रिय स्वभाव के होते हैं। वे रात दिन 'पैसा–पैसा' नहीं सोचते हैं। अधिकारियों की दृष्टि मंत्री को प्रसन्न करने और उंचे पद पर नियुक्ति की ओर होती है। अतः मूल रूप से सरकार को व्यापार में प्रवेश करना ही नहीं चाहिये। इसीलिये इंदिरा गांधी द्वारा बैंक तथा कोयला उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के वांछित परिणाम सामने नहीं आये हैं। इस मूल प्रवृत्ति के बावजूद अल्पसमय के लिये सरकार के लिये उद्योग लगाना उचित होता है। जैसे आज सैटेलाइट प्रक्षेपण को कंपनी बनानी हो तो निजि उद्यमी के लिये कतिपय कठिन है। इस कार्य को सार्वजनिक इकाई के माध्यम से करना चाहिये। कंपनी के सफल होने पर इसे निजि उद्यमी को बेच देना चाहिये। दीर्घकाल तक सरकारी छत्रछाया में व्यापार सफल नहीं होता है। इस विषय में अपवादों से भ्रमित नहीं होना चाहिये।

आज जो सार्वजनिक इकाइयां लाभ कमा रही हैं वो अधिकतर मोनोपोली क्षेत्र में है जैसे आयल इंडिया अथवा विशाल पूंजी के कारण चल रही है जैसे स्टेट बैंक आफ इंडिया। सामान्यतः निजि प्रतिस्पर्धा के शुरू होने के बाद सरकारी कम्पनियां घाटे में चलने लगती हैं जैसे एयर इंडिया, महानगर टेलिफोननिगम एवं प्रसार भारती। एयर इंडिया ने 1997 के पहले के 47 वर्षों में 37 वर्षों में लाभ कमाये। परन्तु इसके बाद निजी प्रतिस्पर्धा शुरू होने पर कम्पनी लगातार डूबती जा रही है। सार्वजनिक इकाइयों के इस खस्ताहाल को सहज वास्तविकता मानना चाहिये। इन्हे लाभप्रद बनाना लगभग असंभव है चूंकि मंत्रियों एवं अधिकारियों का स्वभाव ही व्यापार के अनुकूल नहीं होता है। इन राभी कम्पनियों का समय रहते निजिकरण कर देना चाहिये। सरकार का कर्तव्य निजि क्षेत्रों को सही दिशा देने का है न कि इन्हें स्वयं करने का जैसे कोच स्वयं बल्लेबाजी पर उतारू हो जाये तो टीम निश्चित ही हार जाएगी। ❑

एयर इंडिया के उच्च अधिकारी ने कहा कि सरकारी अधिकारियों की मांगों से मैं इतना परेशान हूं कि लगता है कि मेरे 100 बॉस हैं। ऐसे में शीर्ष अधिकारियों के लिये आसान होता है कि मंत्रियों के साथ मिलकर वे भी कम्पनी का दोहन करें। यह परिस्थिति केवल एयर इंडिया की ही नहीं है तमाम सार्वजनिक इकाइयों की है। महानगर टेलिफोन निगम एवं प्रसार भारती भी इसी समस्या से जूझते हुये घाटे में चल रहे हैं।

लेख

भारतीय परिवार

पहले संयुक्त परिवार में आठ–दस व्यक्ति कम से कम रहते ही थे। परंतु आज परिवार में तीन या चार व्यक्ति ही नजर आएंगे। औद्योगीकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण के कारण होने वाले परिवर्तनों से बढ़ी हुई दैनिक आवश्यकताओं की पूर्त्ति अकेले व्यक्ति के वेतन से संभव नहीं है। अतएव महिलाये की अर्थार्जन हेतु घर से बाहर निकलने लगी है। बरसों से वह पारंपरिक व्यवसाय एवं कृषि के कार्य में सहयोग करती रही है। परिवार को सम्हालकर किए गए ये कार्य बचे हुये समय के कार्य माने जाते थे।

■ रेणु पुराणिक

अर्थववेदिय पृथ्वी शुरू संसार की प्रथम रचना है, जिसमें प्रकृति और पृथ्वी के विषय में एक माँ व उसके बच्चे के परिवार की कल्पना की गई है। उस समय "एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, सर्वभूत हतो रताः"। एवं वसुधैव कुटुम्बकम् जैसे महान सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। परंतु आज संसार में भौतिकवाद और अध्यातावाद का परस्पर सर्घष चल रहा है। केवल भौतिकवाद के आधार पर विश्व शांति की नींव किसी भी प्रकार से ठोस और दृढ़ नहीं हो सकती है।

पश्चिमी सभ्यता की नकल में वेषभूषा, खान–पान, रहन–सहन, आचार–व्यवहार एवं मौजमस्ती के कारण भारत में आज संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। संयुवत परिवार की अवधारणा के कारण राष्ट्र सैकड़ों वर्षों की पराधीनता के वाद भी विश्व में अपने आपको स्थापित किए हुए है। संयुक्त परिवार का व्यक्ति पहले परिवार, फिर समाज और फिर राष्ट्र का निर्माण करता है। संयुक्त परिवार, एक वट वृक्ष है, जिससे फल एवं छाया दोनों प्राप्त होता है।

परिवार में साधारणंतया पति–पत्नी और बच्चों का समूह रहता है, जिसमें विवाह तथा दत्तक प्रथा द्वारा स्वीकृत व्यक्ति भी सम्मिलित रहता है। सभी समाजों में बच्चों का जन्म और पालन–पोषण परिवार में ही होता है। बच्चों को संस्कारित करने और समाज के आचार व्यवहार में दीक्षित करने का काम मुख्य रूप से परिवार में ही होता है। इसके द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। व्यक्ति की सामाजिक मर्यादा बहुत कुछ परिवार से ही निर्धारित होती है। व्यक्ति का परिचय मुख्यतः उसके परिवार और खान–दान के आधार पर होता है।

संसार के विभिन्न प्रदेशों और भिन्न–भिन्न कालों में यद्यपि रचना, आकार, संबंध और कार्य की गति आदि अलग–अलग होने के कारण, इनकी कार्य पद्धति और आचार व्यवहार की दृष्टि से

परिवार समाज का घटक है। यदि परिवार में स्थिरता होगी तो समाज व्यवस्था दृढ़ होगी। समाज स्थिर व दृढ़ होगा तो राष्ट्र सुदृढ़ होगा। परिवार में स्थायित्व महिला के कारण ही आता है। फिर वह गृहिणी हो या चाहे अर्थार्जन करने वाली। वह समन्वयक की भूमिका का निर्वाह करती है। प्रायः वह समाज व्यवस्था बनाए रखने की महान जिम्मेदारी सहजता से निभाती है।

महिलाओं को परिवार की धुरी माना जाता है, अतएव वर्तमान समय में महिलाएं ही सजगता एवं सहनशीलता से परिवार को अपनत्व और दृढ़ता प्रदान करके बिखरने से बचाने में सक्षम है।

परिवार के अनेक भेद है परंतु यह उपयुक्त कार्य सर्वदेशिक और सर्वकालिक है। उसमें देश, काल, परिस्थिति और प्रथा आदि के भेद से एक या अनेक पीढ़ियों का होना संभव है। उसके सदस्य एक पारिवारिक अनुशासन व्यवस्था के अतिरिक्त पति–पत्नी और बच्चों, भाई–बहन, पितामह–मातामह, चाचा–चाची, सास–बहु, पौत्र–पौत्री, भतीजे–भतीजी जैसे संबंधों के साथ कर्तव्यों और अधिकारों से परस्पर आबद्ध रहते हैं। अन्य समाज सामाजिक समूहों के संदर्भ में घनिष्टतम संबंधों के साथ समूहों के रूप में रहते हैं।

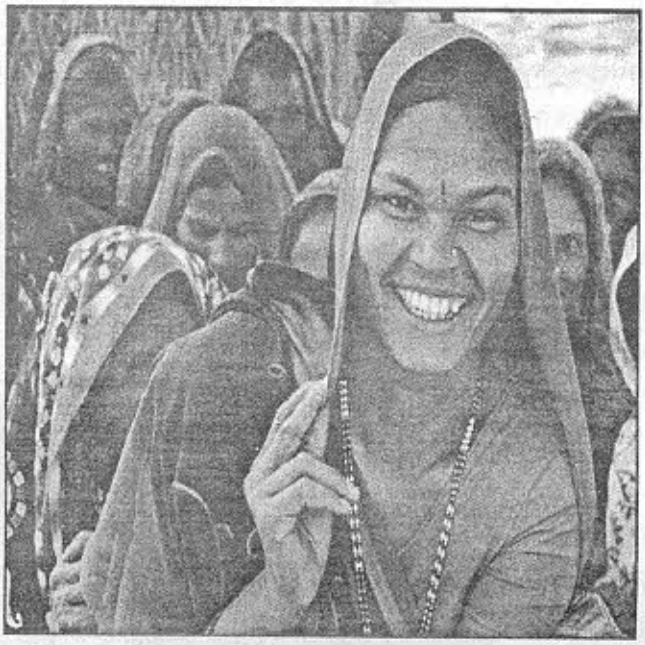

भारतीय परिवार की मर्यादायें और आदर्श परंपरागत है। संसार और मानव समाज की संभवतः सबसे पहली परिवार संस्था आधुनिक दौर में बड़े संकटों से घिरी हुई है। पहले परिवार से व्यक्ति की पहचान होती थी, लेकिन अब परिवार का महत्व घट गया है। व्यक्ति का महत्व आवश्यकता से अधिक हो गया है। परिवार का विघटन हो रहा है। बाजारीकरण ने सामाजिक ढाँचे को तोड़कर रख दिया है।

बाजार के आकर्षण के कारण व्यक्ति के स्वयं के व्यय बढ़ते जा रहे है, जीवन जीने के तरीके बदलने से जीवन संकटमय होता जा रहा है। ऐसे में परिवार का बिखरना निश्चित है। जिस तरह गाँव व कस्बे के रहने वाले लोग दिल्ली, मुम्बई या विदेशों में अपनी जीविका के लिये रह रहे अपने पुत्रों के पास अधिक दिन नहीं रूक सकते है, ठीक इसी प्रकार महानगरों में रहने वाले लोग लंदन, अमेरिका में रह रहे अपने पुत्रोव पौत्रों के साथ अधिक दिन नहीं रह सकते है।

परिवार की कमी उस समय बहुत अखरती है, जब कोई आर्थिक या सामाजिक संकट में होते है। ऐसे वक्त ना कोई परिजन पास में होता है जो काम आ सके। पड़ौसी के पास समय नहीं रहता जिसके पास जाकर अपना दुःख–दर्द कह सके। औद्योगिकरण और वैश्वीकरण के चलते संयुक्त परिवार की संभावना दूर की कौड़ी लगती है। पश्चिमी शैली के समान जीवन–जीने की ओर झुकाव बढ़ता ही जा रहा है।

भारतीय परिवार में व्यक्ति की क्षमतानुसार अर्थाजर्न होता है। उससे पहले समय ने संयुक्त परिवार में पारिवारिक संग्रहित धन का प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकतानुसार व्यय किया जाता था। आज परिवार की व्याख्या बदल गई है। संयुक्त परिवार के स्थान पर एक से चार परिवार बन गए हैं। पहले संयुक्त परिवार में आठ–दस व्यक्ति कम से कम रहते ही थे। परंतु आज परिवार में तीन या चार व्यक्ति ही नजर आएंगे। औद्योगीकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण के कारण होने वाले परिवर्तनों से बढ़ी हुई दैनिक आवश्यकताओं की पूर्त्ति अकेले व्यक्ति के वेतन से संभव नहीं है। अतएव महिलाये की अर्थार्जन हेतु घर से बाहर निकलने लगी है। बरसों से वह पारंपरिक व्यवसाय एवं कृषि के कार्य में सहयोग करती रही है। परिवार को सम्हालकर किए गए ये कार्य बचे हुये समय के कार्य माने जाते थे।

परिवार समाज का घटक है। यदि परिवार में स्थिरता होगी तो समाज व्यवस्था दृढ़ होगी। समाज स्थिर व दृढ़ होगा तो राष्ट्र सुदृढ़ होगा। परिवार में स्थायित्व महिला के कारण ही आता है। फिर वह गृहिणी हो या चाहे अर्थार्जन करने वाली। वह समन्वयक की भूमिका का निर्वाह करती है। पयार्य रूप में वह समाज व्यवस्था बनाए रखने की महान जिम्मेदारी सहजता से निभाती है। महिलाओं को परिवार की धुरी माना जाता है, अतएव वर्तमान समय में महिलाएं ही सजगता एवं सहनशीलता से परिवार को अपनत्व और दृढ़ता प्रदान करके बिखरने से बचाने में सक्षम है। ❑

पर्यावरण एवं स्वास्थ्य - आयुर्वेदीय दृष्टिकोण

व्यक्ति के स्वास्थ्य के उसके चारों ओर का पर्यावरण (वह वातावरण जिसमें वह रह रहा है) प्रभावित करता है। आयुर्वेद व्यक्ति और समाज (लोक एवं पुरुष) में साम्य (एकरूपता) में विश्वास रखता है। आयुर्वेद के अनुसार जिस प्रकार सूर्य (ताप या अग्नि), सोम (जल अथवा चन्द्रमा) तथा वायु इस संसार को धारण करते हैं इसी प्रकार वातदोष (जगतव्यापी वायु का प्रतिनिधि) पित्तदोष (अग्नि अथवा सूर्य का प्रतिनिधि) तथा कफदोष (जल शीतल तत्वों का प्रतिनिधि) शरीर को धारण करता है।

■ डॉ. योगेश चन्द्र मिश्र

भारतीय संस्कृति के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य चार पुरुषार्थ अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना है। इस सभी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को रोग रहित होना अनिवार्य है क्योंकि रुग्ण शरीर से विभिन्न कार्यों का उचित संपादन संभव नहीं है। इसीलिए महर्षि चरक ने चरक संहिता के प्रारंभ में ही स्पष्ट रूप से कहा है –

धर्मार्थ काम मोक्षाणाम् आरोग्यं मूलमुत्तमम्।

रोगास्तस्यापहर्तारो श्रेयसो जीवितस्य च।

अर्थात् धर्म (सत् एवं पवित्र कार्य), अर्थ (विभिन्न प्रकार की साधन सामग्री तथा धन), काम (विभिन्न लौकिक तथा संतान संबंधी कामनाएं), मोक्ष (असीम तथा कभी नष्ट न होने वाला सुख)।

इन चार पुरुषार्थों को प्राप्त करने में आरोग्य ही मूल कारण है, इसके विपरीत रोग उस श्रेय (आरोग्य अथवा सुख या चार पुरुषार्थों) तथा जीवन को नष्ट करने वाला है।

व्यक्ति स्वस्थ और सुखी रहे इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए आयुर्वेद में सुखायु की योजना दी गई है किंतु व्यक्ति केवल अपने सुख तक ही सीमित न रह जाए इस हेतु एक दूसरा शब्द हितायु भी आयुर्वेद ने स्वीकार किया है। हितायु का अर्थ है कि स्वस्थ एवं सुखी व्यक्ति समाज के लिए भी हितकर तथा उपयोगी रहे। इसके विपरीत आयु को दुःखायु तथा अहितकर का विशद वर्णन आयुर्वेद ग्रंथों में उपलब्ध है।

इस विवरण को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि आयुर्वेद उस भारतीय चिंतन के स्वीकार करके चलता है कि व्यक्ति और समाज हित एक दूसरे के विरूद्ध नहीं हो सकते। वे वास्तव में एक दूसरे पर आश्रित तथा पूरक है। सृष्टि में हमें चार स्तर अथवा सत्ताएं व दृष्टिगोचर होती है।

(1) व्यष्टि (व्यक्ति); (2) समष्टि (समाज); (3) सृष्टि (दृश्यमान जगत); (4) परमेष्टि (ईश्वर या परम चैतन्य सत्ता)।

यह सभी सत्ताएं अलग–अलग न होकर एक ही सत्ता के परिवर्धित रूप हैं। इसी क्रम में आयुर्वेद में 'हितायु' की कल्पना दी गई और अपेक्षा की गई कि व्यक्ति में ऐसी संवेदनशीलता तथा सद्गुणों का विकास हो जिससे वह समाज के लिए हितकर कार्य करता हुआ सम्पूर्ण सृष्टि तक आत्मीयता का विकास कर सके तथा परमसत्ता के साथ एकाकार हो सके। इसी सत्य को दर्शन में नर से नारायण बनाने की प्रक्रिया कहकर स्वीकार किया गया।

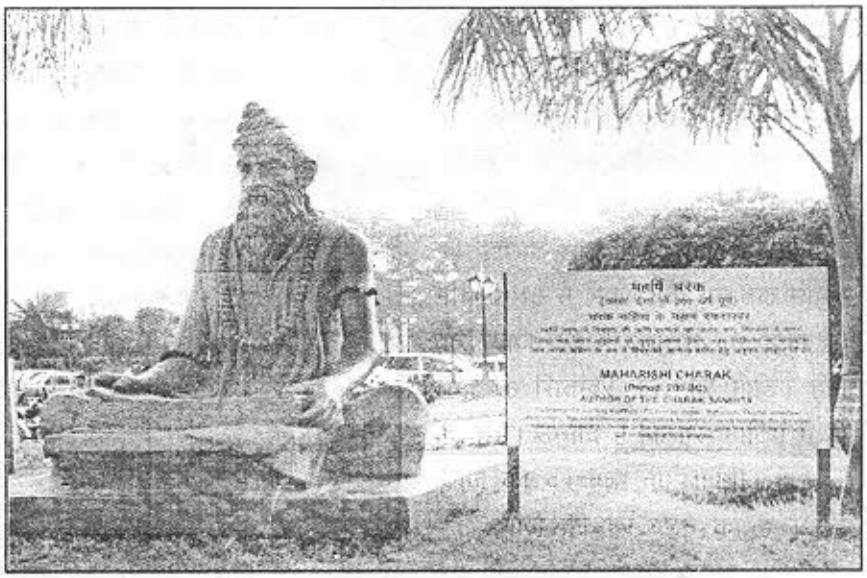

व्यक्ति के स्वास्थ्य के उसके चारों ओर का पर्यावरण (वह वातावरण जिसमें वह रह रहा है) प्रभावित करता है। आयुर्वेद व्यक्ति और समाज (लोक एवं पुरुष) में साम्य (एकरूपता) में विश्वास रखता है। आयुर्वेद के अनुसार जिस प्रकार सूर्य (ताप या अग्नि), सोम (जल अथवा चन्द्रमा) तथा वायु इस संसार को धारण करते हैं इसी प्रकार वातदोष (जगतव्यापी वायु का प्रतिनिधि) पित्तदोष (अग्नि अथवा सूर्य का

प्रतिनिधि) तथा कफदोष (जल शीतल तत्वों का प्रतिनिधि) शरीर को धारण करता है।

जब तक जल तथा वायु, काल तथा देश (भूमि) अदूषित अवस्था में हैं तब तक यह व्यक्ति को स्वस्थ्य रखने में सहायता करते हैं किंतु जब यह दूषित हो जाते हैं तब भयंकर रोगों का कारण बनते हैं। इसी समस्या को वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण नाम से जाना जाता है।

चरक संहिता और पर्यावरण प्रदूषण

सामान्यतया पर्यावरण प्रदूषण को आधुनिक काल की ही समस्या समझा जाता है किंतु प्राचीन काल से ही भारतीय विद्वानों ने प्रकृति चक्र के स्वाभाविक संचालन के द्वारा विभिन्न तत्वों के संरक्षण तथा संवधग्न के उपायों पर गंभीर रूप से विचार किया था। प्राचीन भारतीय संस्कृति में भोग के स्थान पर यज्ञपरक संस्कृति का आग्रह किया गया है। श्रीमद्भगवद्गीता में व्यक्ति की सुख समृद्धि का कारण देवताओं की प्रसन्नता को बतलाया गया है तथा देवताओं की प्रसन्नता का कारण यहां प्रकृति का संरक्षण बतलाया गया है (गीता 3/12)। यहां भौतिक यज्ञचक्र का वर्णन करते हुए कहा गया है :–

संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य (वर्षा) से होती है। पर्जन्य (बादल) यज्ञ द्वारा उत्पन्न होते हैं और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं। भगवान श्रीकृष्ण हमें स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हैं कि यज्ञ द्वारा देवताओं (दैवी गुण सम्पदा) की उन्नति करो। वे देवता (सद्गुण) तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस प्रकार परस्पर वृद्धि करते हुए श्रेष्ठतम् लक्ष्य (परमश्रेय) को प्राप्त करना चाहिए। (गीता 3/12) यज्ञ से बचे हुए अन्न (प्रसादअंश) का सेवन सभी पापों से मुक्ति प्रदान करता है जबकि जो लोग केवल स्वार्थ (भोग) में लिप्त रहते हैं वे सभी पाप (आध्यात्मिक अवनति का मार्ग) के ही भागी होते हैं।

गीता के इस सूत्र को आयुर्वेद के श्रेष्ठ आचार्य चरक ने व्यक्तिगत और सामूहिक रोगों की उत्पत्ति के संदर्भ में विशद रूप से स्वीकार किया है। चरक संहिता विमान स्थान में एक अध्याय है जनपदोध्वसीय अध्याय। जनपद उद्धवंस का तात्पर्य है ऐसी व्याधियां जो एक साथ सामूहिक रूप से अनेक लोगों को अस्वस्थ करने तथा उन्हें मृत्यु के मुख में ढकेलने में सक्षम हो। आधुनिक काल में इस प्रकार की व्याधियों को Epidemic disease कहा जाता है।

प्रश्न यह उठता है कि जब समाज में व्यक्तियों की प्रकृतियां (वातज, पित्तज एवं कफज) अलग–अलग होती हैं तथा उनके आहार, शारीरिक संरचना, बल, सात्म्य, मानसिक प्रकृतियाँ (सात्विक राजस एवं तामस) आयु आदि अलग–अलग होने पर भी सभी लोग एक ही समय में रोगी क्यों हो जाते है। इस प्रश्न के उत्तर में संहिताकार ने जो उत्तर दिया वह वर्तमान समय के पर्यावरण प्रदूषण से पूर्णरूप से साम्य रखता है। उत्तर में कहा गया कि सभी व्यक्तियों की प्रकृति, आयु, बल आदि अलग–अलग होने पर भी कुछ भाव सभी के लिए समान होते हैं और जब इन भावों में विकृति उत्पन्न होते है तब सभी लोग प्रभावित होते हैं। निम्न चार भाव समान रूप से विकृत हो सकते हैं:– (1) वायु; (2) जल; (3) देश; (4) काल।

वायु प्रदूषण के लक्षण

(1) ऋतु विपरीत वायु (शीत ऋतु में अत्यंत उष्ण वायु); (2) अत्यंत तीव्र गति युक्त वायु (आंधी); (3) अति शीतल वायु; (4) अति उष्ण वायु; (5) अत्यधिक रूक्ष वायु; (6) अत्यंत कर्कश वायु; (7) अत्यंत अभिष्यन्दी वायु; (8) विपरीत दिशाओं से आकर टकराने वाली वायु; (9) कुण्डली युक्त वायु; (10) असात्म्य (दुःखकर) गंध, वाष्प, रेत, धूल तथा धुएं से युक्त वायु।

जल प्रदूषण के लक्षण

(1) अत्यधिक विकृत गंध युक्त; (2) अत्यधिक विकृत चर्ण युक्त; (3) अत्यधिक विकृत रस युक्त; (4) अत्यधिक विकृत स्पर्श युक्त; (5) क्लेद बहुल (जिसमें क्लिन्नता व सड़ांद बहुत हो); (6) जिसे छोड़कर जलचर पक्षी चले गए हों; (7) जिन जलाशयों (तालाब आदि) का जल सूखकर थोड़ा रहा गया हो; (8) जो पीने में अच्छा न लगता हो; (9) जिस जल के स्वभाविक गुण नष्ट हो गए हों।

उस जल को रोगोंत्पादक समझना चाहिए।

विकृत देश (भूमि) का लक्षण

आयुर्वेद में भूमि के आधार पर देश तीन प्रकार के बताए गए हैं :– (1) जांगल देश (वृक्षों की अधिकता वाला); (2) आनूप देश (फल की अधिकता वाला) तथा (3) साधारण देश।

देश शब्द से यहां उस क्षेत्र विशेष की भूमि का ग्रहण करना चाहिए जिस जनपद (जिला प्रांत आदि) में रोगों के माध्यम से विनाश हो रहा है अथवा संभावित है। दूषित भूमि के लक्षण निम्नवत् होते हैं:–

(1) जिस भूमि का वर्ण (काला, भूरा आदि), स्वाद (अत्यधिक क्षारीय – अतः ऊसर भूमि आदि), गंध (पशु वधशाला आदि के कारण सदैव तीव्र दुर्गन्ध युक्त) एवं स्पर्श कीचड़ युक्त अथवा रुक्ष आदि से मुक्त भूमि विकृत मानी जाती है तथा इसमें रोगोंत्पत्ति व्यापक रूप सभी निवासियों के एक साथ रोगग्रस्त कर सकती है।

(2) सांप, हिंस्रजन्तु, मच्छर (मलेरिया या डेंगू आदि का कारण), मक्खी (हैजा, कालरा, आदि का कारण), टिड्डी, उल्लू,

गिद्ध आदि पक्षियों की अधिकता वाला देश स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जहां घास {खरपतवार आदि} लताएं आदि अत्यधिक मात्रा में पैदा होते हों {इस कारण खाद्य सामग्री का उत्पादन घट जाएगा}। वह भूमि भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है।

(3) जिस स्थान पर खड़ी फसल {गेहूं, धान आदि} उसका अनाज अकस्मात ही गिरने लगे तथा {बिना पके ही) सूखकर नष्ट हो जाए।

(4) जहां वायु धूम्रवर्ण की दिखाई दे, अधिक मिल वाले नगरों में चिमनियों से धुआं निकलता रहता है उस क्षेत्र में श्वास आदि फेफड़ों की बीमारियां व्यापक रूप से सभी निवासियों को प्राप्त होती हैं।

(5) जहां पक्षी निरंतर शब्द करते हो तथा कुत्ते ऊंची आवाज में रोते हो।

(6) जिन नगरों अथवा जनपदों में नागरिक धर्म भ्रष्ट हो गए हों तथा नागरिकों ने सत्य, लज्जा शील, सदाचार आदि सद्गुणों को छोड़ दिया हो।

(7) जिन क्षेत्रों में उल्कापात, वज्राघात अधिक मात्रा में होने लगे। भूकम्प अधिक आते हो, इन कारणों से भयंकर शब्द, पृथ्वी के नीचे से ज्वालामुखी आदि इसके कारण वातारण में धूल, गैस आदि। {अणु बम विस्फोट एवं उसके उपरांत की स्थितियों वाला देश} जनपदों ध्वंस की स्थितियों की उत्पत्ति में सहायक होते हैं।

(8) जहां पर जलाशय अत्यंत क्षुब्ध हो तथा ऊंची तरंगे उठती हों। सुनामी आदि तथा बाढ़ के बाद होने वाली महामारियां।

(9) जहां सूर्य चन्द्रमा आदि ग्रह अरुण, ताम्र श्वेत आदि वर्ण के बादलों में छिप जाएं।

उपर्युक्त लक्षणों से युक्त भूमि (देश) लोगों के लिए अहितकर होता है तथा जनपदोध्वंस में सहयोगी होता है।

काल (ऋतु) प्रदूषण

भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत वर्ष में वर्ष को उत्तरायण एवं दक्षिणायन इन दो भागों में बांट कर छः ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। विभिन्न ऋतुओं में होने वाले विशेष लक्षणों के आधार पर उस काल की स्वास्थ्यप्रद ऋतुचर्या का वर्णन आयुर्वेद में वर्णित है। इन ऋतुओं में यदि अत्यधिक उग्र लक्षण दिखें यथा सामान्यतया ग्रीष्म ऋतु में तापमाल लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। प्रदूषण के कारण विगत कुछ वर्षों में तापमान में क्रमशः शनैः शनैः वद्धि होनी प्रारंभ हुई है। यदि यह क्रम बढ़ता रहे अथवा अणु विस्फोट आदि जोकि काल एवं देश प्रदूषण का ही एक कारण/प्रकार है, यह तापक्रम 50 डिग्री सेल्सियस पर या उससे अधिक पहुंच जाये तो मानव के लिए (सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस) जीवन दूभर हो जाएगा। यह लक्षण चूंकि सभी के लिए समान रूप से घातक होंगे अतः जनपदोध्वंस का कारण बनेंगे। अतिवृष्टि और अतिशीत आदि लक्षणों को इसी प्रकार समझा जा सकता है। केवल अतियोग ही नहीं ऋतुओं के लक्षणों का अयोग या हीन योग जैसे ग्रीष्म में बिल्कुल गर्मी न पड़ना, वर्षा ऋतु अवृष्टि तथा शीतकाल में शीत में कमी आदि इसी प्रकार घातक होकर जनपदों के सामूहिक विनाश का कारण बनते हैं।

प्रश्न यह उठता है कि जब समाज में व्यक्तियों की प्रकृतियां (वातज, पित्तज एवं कफज) अलग–अलग होती हैं तथा उनके आहार, शारीरिक संरचना, बल, सात्म्य, मानसिक प्रकृतियाँ (सात्विक राजस एवं तामस) आयु आदि अलग–अलग होने पर भी सभी लोग एक ही समय में रोगी क्यों हो जाते है। इस प्रश्न के उत्तर में संहिताकार ने जो उत्तर दिया वह वर्तमान समय के पर्यावरण प्रदूषण से पूर्णरूप से साम्य रखता है।

वर्तमान काल में स्वास्थ्य के लिए हानिकर प्रदूषणों में ध्वनि प्रदूषण, खाद्य सामग्री में अपमिश्रण तथा बिजली एवं विकिरण जन्य आपदायें आदि प्रमुख हैं।

इन सभी का समावेश आयुर्वेदसम्मत वायु, जल, देश एवं काल प्रदूषणों में किया जा सकता है।

प्रदूषणों की तीव्रता अथवा प्रधानता

सभी प्रकार के प्रदूषण मानव के लिए हानिकारक हैं। उनमें से कुछ से सरलता से बचा भी जा सकता है जैसे जल प्रदूषण की स्थिति में जल को उबाल कर पीना अथवा विभिन्न प्रकार के एक्वागार्ड आदि का प्रयोग कर उससे होने वाली समस्याओं से कुछ मात्रा में बचा जा सकता है। इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए चरक संहिता हमें निम्नवत् निर्देशित करती है :– वायु की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा देश (भूमि) और देश की अपेक्षा काल दुष्परिहार्य (जिनको कठिनाई से छोड़ा जा सके) होता है। अभिप्राय यह है कि सभी प्रदूषण हानिप्रद होने पर भी यद्यपि शुद्ध वायु अर्थात् आक्सीजन युक्त वायु का प्रदूषण होने पर यदि व्यक्ति कुछ समय के लिए दूषित वायु के स्थान को छोड़ कर अथवा कृत्रिम साधनों से नासिका पर वस्त्र आदि लगाकर अथवा आंधी आदि से मुक्त स्थान पर रहकर प्राणघातक संकट से निकल सकता है किंतु जीवन धारण के लिए जल तो पीना ही होगा।

जलप्रदूषण की स्थिति में उसका शोधन कर समस्या पर विजय प्राप्त की जा सकती है किंतु देश को छोड़ना अत्यंत

कठिन है और काल के प्रदूषित होने पर तो उससे बचना सर्वथा असंभव ही है। अतः वायु, जल, देश और काल प्रदूषण को क्रमशः तीव्र तथा घातक माना गया है।

सभी प्रदूषणों का मूल कारण – अधर्म

किसी भी विषय पर गहराई से विचार करना भारतीय चिंतन का वैशिष्ट्य है। चार प्रकार के प्रदूषणों के लक्षणों की चर्चा सुनने मात्रा से शिष्यों की जिज्ञासा शांत नहीं हुई और पुनः प्रश्न उठा कि जनपदोध्वंस उत्पन्न करने वाले वायु, जल, देश तथा काल प्रदूषण का भी मूलकारण क्या है। अग्निवेश नामक शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि आत्रेय ने उत्तर दिया कि वायु, जल, देश और काल की विकृति (प्रदूषण) का मूल कारण अधर्म है और इसका भी कारण है प्रज्ञापराध। यहां यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि धर्म का तात्पर्य भारतीय चिंतन में कोई विशेष पूजा पद्धति नहीं है अपितु विभिन्न व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने वाले सदाचरण व सामाजिक दायित्वबोध आदि को भारतीय चिंतन में धर्म कहा गया है। प्रज्ञा अर्थात् बुद्धि का कार्य है विवेकपूर्ण चिंतन करते हुए व्यक्तिगत उन्नति के ऐसे कार्यों का चिंतन जो कि समाजोपयोगी भी हों। समाज के लिए हितकर (हितायु) आयु का चिंतन ही भारतीय मनीषा एवं आयुर्वेद को अभीष्ट है। जब व्यक्ति अपनी (बुद्धि), धैर्य तथा स्मृति की उपेक्षा करता हुआ कार्य में प्रवृत्त होता है तब उसके कार्य प्रायः अशुभ होते हैं। इसी को आयुर्वेद में प्रज्ञापराध कहा गया है जो सभी दोषों को प्रकुपित करने में मूल कारण है।

इस संदर्भ में चरकसंहिता का वर्णन अत्यंत व्यवहारिक तथा वर्तमान युग के वर्णन जैसा ही प्रतीत होता है।

वायु आदि सभी तत्वों की विगुणता की जड़ अधर्म ही है। अथवा अधर्म का कारण जो पूर्वकृत बुरे कर्म है, उन्हें वायु आदि की विगुणता का कारण कह सकते हैं। पूर्वकृत बुरे कर्म तथा अधर्म दोनों का उत्पत्तिकारण प्रज्ञापराध है। जैसे जब देश नगरनिगम या जनपदों के मुखिया एवं राजा धर्म की परवाह न करते हुए अधर्म से प्रजा के साथ व्यवहार करते हैं तब उनके आश्रित और उपाश्रित पौरजानपद (सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी) उस देश के निवासीगण और व्यापार करने वाले भी उस अधर्म को बढ़ाते हैं। अर्थात् जब मुखिया ही अधर्माचरण करता हो – रिश्वत आदि लेता हो तो उसके नौकर चाकर देखादेखी व अपने मुखिया के पेट को भरने के लिए तथा अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए दूसरों से रिश्वत लेना चाहते हैं व दूसरे अधर्म कार्य करवाना चाहते हैं।

अतः जो व्यापारी अपना लेन–देन उनके साथ करना चाहते हैं वहां के नौकरों को रूपए चढ़ाने पड़ते हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए व्यापारी दूसरी तरह धोखे करते हैं। इस प्रकार रिश्वत देना लेना घूसखोरी, धोखा, असत्य का बाजार गरम हो जाता है। वह बढ़ता हुआ अधर्म धनोपार्जन का गलत मार्ग धर्म अर्थात् सत्य मार्ग को सर्वथा छिपा देता है। जब धर्म लुप्त हो जाता है तब देवता भी उनका त्याग कर देते हैं। उन लुप्तधर्मा धर्मप्रधान देवताओं से छोड़े गये देश जनपद आदि की ऋतुएं विकृत हो जाती हैं, इन्द्र अथवा मेघ यथाकाल जल नहीं बरसाते अथवा विकृत जल बरसता है। वायु ठीक प्रकार से नहीं बहती। पृथ्वी विकृत हो जाती है। जल सूख जाते हैं। औषधियां स्वभाव को छोड़कर विकृत हो जाती हैं तब उनके स्पर्श तथा आहार के दोष से जनपद उजड़ जाते हैं।

उपर्युक्त विवरण को दृष्टिगत करने पर स्पष्ट हो जाता है कि चरक संहिता के संस्करण तथा प्रतिसंस्करण काल से पूर्व समय से लेकर वर्तमान समय तक पर्यावरण प्रदूषण के व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्तर पर दो ही कारण रहे हैं – प्रज्ञापराध एवं अधर्म। आधुनिक काल में भी विकसित कहे जाने वाले राष्ट्रों की तथा अन्य नागरिकों की भोगवृत्ति, स्वार्थवृत्ति तथा मात्र तात्कालिक व्यक्तिगत शारीरिक सुखों की कामना के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय उपभोग (उपयोग नहीं) की प्रवृत्ति पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अधर्म के स्थान पर धर्म अर्थात् व्यक्ति और समाज के प्रति आत्मीयता एवं स्नेह भाव का जागररण तथा विकास के परिपेक्ष्य मानवता का विस्मरण न हो यह आवश्यक है। हमें यह समझना आवश्यक होगा कि प्राणी मात्र का वास्तविक सुख स्वस्थ पर्यावरण में निहित है। वैदिक काल से ही भारतीय चिंतन पर्यावरण की रक्षा हेतु जन–जागरण के लिए सदैव से संकल्पशील रहा है। इसी संकल्प को यजुर्वेद के अ.36 के मंत्र में उपलब्ध है :–

ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापःशान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाःशान्तिब्रह्मः शान्तिः सर्वशान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।

इस मंत्र में भावों का अनुपालन ही चरक में लोक एवं पुरुष की एकरूपता के रूप में स्वीकार किया गया है। इसकी स्वीकार्यता एवं अभिव्यक्ति विश्व को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त कराने में सफल होगा। कठिन होने पर भी यही एक मात्र मार्ग है। प्राचीन आयुर्वेद साहित्य में उपलब्ध पर्यावरण प्रदूषण का विवरण आज के युग में भी समीचीन है। ❑

रपट

पेड़ लगाएं और जंगल को बचाएं

आचार्य धन्वन्तरी अपनी शिक्षा पुरी की तो उनके गुरु ने कहा कि धन्वन्तरी तुम्हारी गुरु दक्षिणा तभी होगी जब तुम जंगल से एक भी अनुपयोगी वृक्ष लाकर हमें दोगे, परिणाम हुआ कि धन्वन्तरी ने बारह वर्षों तक भारत के जंगलों में घूमता रहा और एक भी अनुपयोगी वृक्ष नहीं ला सका। इसलिए हम सभी उपस्थित लोगों से अपील करते हैं कि कोई भी व्यक्ति खड़े वृक्ष को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाएं जंगल में लगे पेड़ के पत्ते को तोड़े उसका व्यवसाय करें लेकिन हरा पेड़ को काटे नहीं। – कौशल किशोर

चिलगड्डा जंगल (13 अगस्त 2011) झारखण्ड। हजारों किसानों ने सैकड़ों वृक्षों में रक्षासूत्र बांधते हुए पूरा जंगल, संस्कृत के इस मंत्र से गुंजायमान हो गया – येन बन्धो वली राजो दानवेन्द्रो महाबलः। तेनत्वाप्रतिवध्नामि रक्षे माचल माचलः। सभा को संबोधित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं किसान नेता श्री कौशल किशोर ने कहा कि भारत के जंगल में कोई भी ऐसा वृक्ष अथवा पौधा नहीं जो मानवहीतकारी न हो यह मैं नहीं आचार्य धन्वन्तरी का कहना है जो भारत के सुश्रुत्र संहिता में उद्धित है। आचार्य धन्वन्तरी अपनी शिक्षा पुरी की तो उनके गुरु ने कहा कि धन्वन्तरी तुम्हारी गुरु दक्षिणा तभी होगी जब तुम जंगल से एक भी अनुपयोगी वृक्ष लाकर हमें दोगे, परिणाम हुआ कि धन्वन्तरी ने बारह वर्षों तक भारत के जंगलों में घूमता रहा और एक भी अनुपयोगी वृक्ष नहीं ला सका। इसलिए हम सभी उपस्थित लोगों से अपील करते हैं कि कोई भी व्यक्ति खड़े वृक्ष को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाएं जंगल में लगे पेड़ के पत्ते को तोड़े उसका व्यवसाय करें लेकिन हरा पेड़ को काटे नहीं।

श्री कौशल ने कहा कि हमको साल भर भोजन करना है तो खेती करें और वर्षों भोजन करना है तो पेड़ लगाएं और जंगल को बचाएं। वर्तमान समय में जंगल का रक्षक वा रक्षक नहीं रह पाया। सरकार उसे वेतन देती है जंगल बचाने के लिए परंतु जंगल उजाड़ने हेतु जितने प्रकार का तिकड़म करने होते है वो किया करते है। नए वृक्ष लगाने में ये रक्षक विदेशी वृक्ष और जल को शोषण करने वाली वृक्ष लगाते है। इसलिए हम लोग जो जंगल में या जंगल के आसपास रहते हैं, ऐसे सभी लोगों से अपील करते हैं कि नीम, करंज, पीपल, बरगद एवं फलहार वृक्ष लगाएं और लगवाने का प्रयास करें। उपस्थित समूहों से अपील करते हुए कहा कि अभी खेती समय प्रारंभ हो रहा है। विगत चार वर्षों से अकाल की स्थिति थी, चार वर्षों के बाद फसल अच्छे हों उसमें खाद का प्रयोग करें जो जैविक हो। रसायनिक खाद का प्रयोग नहीं के बराबर हो।

मुख्य अतिथि प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया, जैनामोड अरुण कुमार राउत ने उपस्थित किसानों से अपील की कि वृक्ष लगाएं तथा जंगल को बचाए। बैंक ऑफ इंडिया और हमसे जो बन पड़ेगा वो मदद करूंगा। मैं भी किसान पुत्र हूँ। गाँव की समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, जिससे आप सबों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके। आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आएं, आपको गाय, भैस, बकरी सभी में हम आपको ऋण उपलब्ध कराएंगे। हमारी शर्त केवल इतना है कि बैंक के पैसे को अपना पैसा समझ कर बैंक को वापस करें जिससे अन्य किसानों को दुबारा ऋण दिया जा सके।

सभा को संबोधित करने वालों में भाकपा माले के प्रखण्ड सचिव अभिविलाष भगत, अखिल भारतीय विधार्थी परिषद् के विनोद कुमार, चिलगड्डा पंचायत परिषद के धीरेन्द्र नाथ साव, महेन्द्र नायक, पद्मलोचन नायक, बासुदेव नाथ महतो, सुमित्रा वाला, रामा मांझी, वैद्यनाथ हांसदा, कमलेश्वर नायक, सूरजदेव महली, राजन सिंह, लालु घासी, आनन्द घासी, मनिरूद्दीन अंसारी ने संबोधित किया।

इससे पूर्व चिलगड्डा गांव से प्रखण्ड के संयोजक पद्मलोचन महतो, खगेन्द्र हांसदा के नेतृत्व में वन बचाने के लिए नारा लगाते हुए शोभा यात्रा के रूप में जंगल तक सैकड़ों किसान पहुंचे। प्रमुख लोगों में उपस्थित – गौरीलाल महतो, लालमोहन मांझी, हरिकृष्ण मंडल, अनिल मंडल, राशविहारी महतो, भागीरथ महतो, बुधनी देवी, चुडमणी देवी, सुजीत मंडल, माणिक मंडल, ईश्वर मांझी धीरन घासी, प्राण मांझी ठाकुर दास नायक, ननकू मांझी, रोहण मांझी, रामप्रसाद महतो, इन्द्रदेव मांझी, सूकू मांझी, धनु मांझी, जगबन्धु मांझी, कौशिल्या देवी, मैना देवी इत्यादि सहित सैकड़ों किसान उपस्थित थे। सभा की अध्यक्षता रामा मांझा ने की एवं धन्यवाद ज्ञापन खगेन्द्र हांसदा ने किया।

स्वदेशी उत्पाद से ही देश का विकास : डॉ. रमन सिंह

स्वदेशी के बिना उद्योग व कृषि सहित किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं की जा सकती।
– मदनदास देवी जी

स्वदेशी को केवल उत्पाद तक सीमित नहीं रखते हुए इसे विचार और व्यवहार में लाने की आवश्यकता है।
– मुरलीधर राव

22 अगस्त, 2011 रायपुर, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने देश के विकास के लिए स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया है। उन्होंने राज्य में स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार–प्रसार के लिए अब तक किए गए सराहनीय प्रयासों को और आगे बढ़ाने के लिए कहा है। न्यू शांतिनगर में स्वदेशी भवन का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इसके लिए स्वदेशी जागरण मंच और सीबीएमडी जैसी संस्थाओं की तारीफ भी की। साथ ही संगवारी योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत फल–सब्जी विक्रेताओं, हाथ ठेला और रिक्शा चालकों को कम ब्याज पर कर्ज (माइक्रो फाइनेंस) उपलब्ध कराया जाएगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में स्वदेशी की अवधारणा की उपयोगिता बताई।

विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मदनदास देवी जी ने राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में स्वदेशी चिंतन को सर्वोपरि बताया। उनका कहना था कि स्वदेशी के बिना उद्योग व कृषि सहित किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं की जा सकती।

अति विशिष्ट अतिथि श्री मुरलीधर राव ने स्वदेशी को केवल उत्पाद तक सीमित नहीं रखते हुए इसे विचार और व्यवहार में लाने की आवश्यकता पर बल दिया।

लोकार्पण समारोह में अन्य विशिष्ट अतिथियों में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, ग्रामीण विकास मंत्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री चन्द्रशेखर साहू, नगरीय विकास मंत्री राजेश मूणत, महापौर डॉ. किरणमयी नायक स्वदेशी जागरण मंच के प्रदेश संयोजक व दीनदयाल शोधपीठ के अध्यक्ष दिनकर केशव भाखरे, प्रांत संयोजक डॉ. राजेन्द्र दुबे, नगरनिगम के सभापति संजय श्रीवास्तव, सीबीएमडी के निदेशक भोलानाथ विज, अनिल गचके आदि मौजूद थे।

कार्यक्रम का संचालन शताब्दी पाण्डेय व आभार श्री भाखरे ने किया।

स्वदेशी जुटान

3–4 सितंबर, 2011, आध्यात्म साधना केंद्र, छतरपुर, दिल्ली

स्वदेशी जुटान का वक्तत्व

- दिल्ली के छतरपुर स्थित आध्यात्म साधना केंद्र में दो दिनों (3–4 सितंबर, 2011) का स्वदेशी जुटान ज्वलंत राष्ट्रीय समस्याओं पर सार्थक मंथन से पूरा हुआ।
- इन राष्ट्रीय समस्याओं में भ्रष्टाचार के संघर्ष को पहली वरीयता देनी होगी। हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने की लड़ाई राजनीतिक है। इसे अराजनीतिक समाज के सहयोग से भी लड़ना होगा, लेकिन दिशा राजनीतिक ही रहनी चाहिए। यह समझ उसका आधार होगी कि यह मुद्दा राजनीतिक है।
- भ्रष्टाचार अपरिभाषित नहीं है। उसकी एक कानूनी परिभाषा है। सत्ता का अपने स्वार्थ के लिए दुरूपयोग ही भ्रष्टाचार है।
- भ्रष्टाचार और काले धन का अभिन्न संबंध है। काले धन का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में जमा है। उसे वापस लाने के लिए सघन संघर्ष छेड़ना होगा।
- भ्रष्टाचार और कालाधन इस राज्य व्यवस्था से उपजा है, जो औपनिवेशिक लूटतंत्र के चलते रहने का एक परिणाम है। इस राज्यतंत्र के अनेक दुष्परिणाम हमारे जन जीवन को अभिशप्त किए हुए है। हमें यह गांठ बांधनी होगी कि जब तक यह पूरी व्यवस्था नही बदलती तब तक यह संघर्ष चले। क्योंकि मौजूदा राज्य व्यवस्था ही लूट तंत्र को संरक्षण दे रही है। इसी अर्थ में यह व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष है।
- हमारा मानना है कि कालाधन घुन की तरह हमारे जन–जीवन में लगा हुआ है। इसका निदान सनातन धर्म है। आज का युग धर्म लोकतंत्र है। स्वदेशी जुटान को आप सर्वसमावेशी दशनामी अखाड़ा समझकर रणक्षेत्र में कूदें।
- यह भी समझ लेना जरूरी है कि कालेधन के कारण देश की सुरक्षा अर्थव्यवस्था, उत्पादन–संबंध बल्कि उनका आकार सुरसा की तरह बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक विकल्प का हनुमान लघुरूप में ही सही समाधानकारक हो सकता है।
- यह संभव है अगर राष्ट्रीयता की चेतना को प्रखर किया जा सके। विदेशी मॉडल की नकल बंद हो। यूरोप में पूंजीवाद का विकल्प न्यूकेपिटिलिज्म माना जा रहा है, जिसमें राज्य का हस्तक्षेप एक कुंजी बन गया है। भारत को अपनी राज्य व्यवस्था की खोज करनी है, उदाहरण स्वरूप 1954 ई. में जे.पी. इस खोज के क्रम सुझाव रखे थे। देसी सोच और विकेन्द्रीकरण को इस व्यवस्था का आधार माना जा सकता है। वास्तव में विकास का पश्चिमी मॉडल विद्यमान सामाजिक असमानताओं एवं विकृतियों को और अधिक बढ़ा रहा है। उनका भी निराकरण करना होगा।
- इस तरह के प्रयासों के लिए जरूरी है कि राष्ट्रवादी शक्तियां एकजुट हों। किसान, मजदूर और दलित अभी भी शोषण के शिकार हैं। सबको साथ लेकर समवेत संघर्ष खड़ा करना होगा। भेदभाव को तिलांजलि देनी होगी, तभी समय का रथ गतिमान हो सकेगा।
- इस एकजुटता को एक प्रक्रिया में बदलना संभव है। यह प्रक्रिया दो स्तरों पर चलेगी – बौद्धिक और व्यावहारिक। इस स्वदेशी जुटान की सार्थकता इसमें है कि सभी वर्गों, विचारों, मान्यताओं के लोगों को एकजुट करने का प्रयास हो। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के प्रति संकल्पबद्ध होने के लिए क्षेत्रीय जुटानों का आयोजन हो, संघर्ष की नई धारा खड़ी हो।

आर्थिक विकास मॉडल पर

हैदराबाद में मंच की राष्ट्रीय गोष्ठी

आर्थिक विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक उन्नति नहीं होना चाहिए और ना ही जीडीपी की दर को आर्थिक विकास का पैमाना माना जाना चाहिए। आर्थिक विकास में कृषि विकास को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए।

– गोविंदाचार्य

विकास की अवधारणा सिर्फ जीडीपी नहीं हो सकती। बल्कि विकास का आशय समृद्धि और संस्कृति में बेहतर संतुलन है। पश्चिम में भले ही भोग की संस्कृति को ही आर्थिक गतिविधियों का केंद्र माना गया हो लेकिन हमारे यहां भोग के साथ–साथ त्याग का भी महत्व है।

समद्धि भौतिक सुख का धोतक है तो संस्कृति आंतरिक सुख की प्रतीक है। ये विचार माननीय के.एन. गोविंदाचार्य ने व्यक्त हैदराबाद में आयोजित स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक विकास मॉडल विषय पर राष्ट्रीय गोष्ठी में व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि पश्चिम की न तो भाषा मानवीय संवेदना को ठीक से व्यक्त कर पाती है और न वहां के आर्थिक और सामाजिक मॉडल ही मानव जाति के लिए पूरी तरह उपयुक्त हैं।

उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा अपने आप में इतनी संकुचित है कि उसके पास पाप और पुण्य को परिभाषित करने वाले अलग अलग पूण अर्थ देने वाले शब्द नहीं है। अंग्रेजी में पाप के लिए एक शब्द है सिन, जबकि पुण्य के लिए कोई शब्द ही नहीं है। क्योंकि पश्चिम में धर्म और मजहब में कोई अंतर ही नहीं है। वे तो केवल 'सिन' जानते हैं। जबकि हमारी संस्कृत अपने आप में परिपूर्ण भाषा है। संस्कृत के बहुत सारे शब्द अंग्रेजी भाषा ने ले लिए हैं, लेकिन संस्कृत ने अंग्रेजी या अन्य किसी विदेशी भाषा से कोई शब्द नहीं लिए हैं। इसी तरह भारत के समान कोई दूसरा देश नहीं है।

आज भले ही अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए पश्चिम के देश दुनिया को एक वैश्विक गांव के रूप में परिभाषित करते हों लेकिन हमारे यहां तो प्राचीन काल से वसुधैव कुटंबकम प्रचलित है। यानी पूरी दुनिया हमारी कुटुंब है।

> **अमरीका की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, फिर भी अमरीका प्रशासन इसे मानने को तैयार नहीं है। अमरीका पूरी तरह कर्ज से दबा हुआ है। अकेले चीन ने उसे 1.2 खरब डॉलर का कर्जा दिया हुआ है। और अब चीन उसे सलाह दे रहा है कि वह अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए पैसे खर्च न करे।**

श्री गोविंदाचार्य ने कहा कि आर्थिक विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक उन्नति नहीं होना चाहिए और ना ही जीडीपी की दर को आर्थिक विकास का पैमाना माना जाना चाहिए। आर्थिक विकास में कृषि विकास को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। हमें पूंजीकरण के बजाय समाजीकरण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें सत्ता प्रमुख नहीं होना चाहिए।

वास्तविक विकास मॉडल में समाज को आगे और सत्ता को पीछे होना चाहिए। संस्कृति से ही समाज राजनीति और देश को नियंत्रित किया जाना चाहिए। बाह्य विकास के बजाय आंतरिक विकास पर जोर होना चाहिए। श्री एम. आर. वेंकटेश ने कहा कि अमरीका की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, फिर भी अमरीका प्रशासन इसे मानने को तैयार नहीं है। अमरीका पूरी तरह कर्ज से दबा हुआ है। अकेले चीन ने उसे 1.2 खरब डॉलर का कर्जा दिया हुआ है और अब चीन उसे सलाह दे रहा है कि वह अपनी सैन्य क्षमता को बढाने के लिए पैसे खर्च न करे।

मंच के प्रदेश संयोजक वी. साई प्रसाद ने आगाह किया कि देश के खुदरा बाजार पर विदेशी कंपनियां गहरी नजरें गड़ाई हुई हैं। उन्होंने कहा कि भारत का खुदरा व्यापार लगभग 20 हजार करोड रुपये का है। इसलिए वे लोग इस पर कब्जा जमाने के लिए हर संभव षडयंत्र कर रहे हैं। ❑